वर्ष-11, अंक-4, जनवरी-2026

मूल्यः ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

मिलेनियल युवाओं पर भाजपा का फोकस

देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश

जहां उत्तर प्रदेश लाइन वहीं से

प्रति वर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन

गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में अग्रणी

करके दिखाए जो डबल इंजन सरकार है वो

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

वर्ष- 11 अंक- 4

जनवरी-2026

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक

अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक

स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार

विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी

डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड

रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार

कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

अन्दर के पेजों में...

कवर स्टोरी पेज-28

नया साल: आत्ममंथन, संकल्प और मोदी सरकार की अग्नि-परीक्षा — पेज 05

लोकतंत्र की आत्मा हैं न्याय, समता व बंधुता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ — पेज 08

महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर नेता रहे अजित पवार की राजनीतिक विरासत का कौन बनेगा उत्तराधिकारी? — पेज 12

'एक भारत, एक कानून' की नीतिगत कसौटी के सियासी निहितार्थ — पेज 14

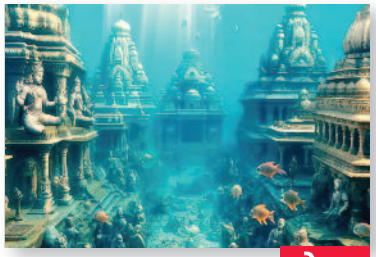

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका कल्पना नहीं हकीकत है — पेज 38

साइना नेहवाल की चुपचाप विदाई ने खेल जगत को सन्न कर दिया — पेज 54

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 / 9813221734 पर सम्पर्क करें।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता

ललित कुमार
सम्पादक

बदलते दौर में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक समझौता होने वाला है, जिसकी घोषणा द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में किए जाने की संभावना है। इसके तहत रक्षा क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा एवं आतंक के खिलाफ साझा मोचेर्बंदी, भारतीय और यूरोपीय नागरिकों की आसान आवाजाही तथा वस्त्र उद्योग एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। यह समझौता इसलिए भी अहम होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे अमेरिका की शुल्क नीति के प्रभाव से निपटने के लिए भारत और यूरोपीय देशों के बीच साझा एवं व्यापक दृष्टिकोण विकसित होगा। अनुमान है कि इस समझौते से दो अरब लोगों का एक ऐसा बाजार बनेगा, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा। इससे न केवल भारत के निर्यात को गति मिलेगी, बल्कि यहां के पेशेवरों के लिए यूरोपीय देशों में रोजगार पाने का रास्ता भी सुगम हो जाएगा। इसमें दोराय नहीं कि अमेरिका की ओर से भारत पर पचास फीसद शुल्क लगाए जाने के बाद देश का निर्यात कारोबार प्रभावित हुआ है।

नतीजतन, भारत अपने उत्पादों के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में वैकल्पिक बाजार तलाशने के हर संभव प्रयास में जुटा है। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार एवं व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले ब्रिटेन और ओमान के साथ व्यापार समझौते किए गए थे। यूरोपीय संघ के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पहली बार वर्ष 2007 में शुरू की थी, लेकिन कुछ मसलों पर आपसी सहमति न बनने के कारण वर्ष 2013 में बातचीत स्थगित कर दी गई थी।

जून, 2022 में वार्ता को फिर से आगे बढ़ाया गया, जो निर्णायक रही। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में गुणात्मक बदलाव लाएगा। माना जा रहा है कि शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी देने के अलावा दोनों पक्ष रक्षा ढांचागत समझौता और एक रणनीतिक एजंडा भी प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। प्रस्तावित सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और गहरा करने में सहायक होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आपसी तालमेल बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय संघ के ह्यसेफह्न (सिक्योरिटी एक्शन फार यूरोप) कार्यक्रम में भागीदारी के रास्ते खुलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक समझौते से देश के वस्त्र निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा परिधान बाजार है। वर्तमान में भारत इस क्षेत्र में 4.5 अरब डालर से अधिक मूल्य के परिधानों का निर्यात करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार लगभग 136 अरब अमेरिकी डालर का था, जिसमें निर्यात की हिस्सेदारी करीब 76 अरब अमेरिकी डालर थी। अब बहु-प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगने से निश्चित रूप से द्विपक्षीय व्यापार को एक नई दिशा मिलेगी और भारत के निर्यात कारोबार पर अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक समझौता होने वाला है, जिसकी घोषणा द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में किए जाने की संभावना है। इसके तहत रक्षा क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा एवं आतंक के खिलाफ साझा मोचेर्बंदी, भारतीय और यूरोपीय नागरिकों की आसान आवाजाही तथा वस्त्र उद्योग एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुलेंगे।

नया साल: आत्ममंथन, संकल्प और मोदी सरकार की अग्नि-परीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में जिस प्रकार से अनेक चुनौतियों का सामना किया, उसी प्रकार भावी वर्ष में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहा जाए तो साल 2026 में नरेंद्र मोदी को अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा और आने वाला वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा व पीएम मोदी के लिये बेहद अहम है।

संजीव कुमार

नया साल एक नए सवेरे की तरह है, जो हर वर्ष एक बार आता है और अपने साथ नई शुरूआत की संभावनाएं लेकर आता है। समय के साथ वह अपने चरम पर पहुंचता है और फिर धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। यही क्रम एक निरंतर अनुभव है, जिसे इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। यह निरंतरता ही प्रकृति और जीवन का परम सत्य है। नए वर्ष की शुरूआत प्रत्येक व्यक्ति को पिछले साल के निरंतर प्रवाह और अनुभवों से सीख लेकर अच्छे कार्यों से करनी चाहिए। यह समय आत्मचिंतन का होता है, जब हमें अपने अच्छे-बुरे कार्यों का मूल्यांकन कर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए।

नए साल की शुरूआत सद्कर्मों, सकारात्मक सोच और स्पष्ट दिशा के साथ करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। नया वर्ष हर व्यक्ति के लिये बीते हुए वर्ष की सफलताओं और उपलब्धियों के साथ.साथ कमियों और गलतियों का मूल्यांकन करने का समय है। यह हमें अपने आप को भावी वर्ष के लिये योजना बनाने, कार्य करने तथा आगामी वर्ष के लिये नये लक्ष्य तय करने का अवसर प्रदान करता है। नये साल की शुरूआत में हर व्यक्ति को भावी वर्ष के लिये नये लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने की रणनीति बनानी चाहिए। जिससे कि अवसरों को सफलता में बदला जा सके। यदि व्यक्ति

अपने जीवन के आरंभ में ही अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो सफलता की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्य हमें अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को नए वर्ष की शुरूआत में वर्ष भर के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, ताकि आने वाले समय में वह अपने लक्ष्य के लिए किए गए सत्कर्मों और प्रयासों के माध्यम से निरंतर विकास करता हुआ अपने जीवन के चरम और शिखर तक पहुँच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, साथ-साथ अनेक सफलताएँ भी पायी हैं। इन सफलताओं और उपलब्धियों में मोदी सरकार को अपनी गलतियों और कमियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। बल्कि अपनी गलतियों और कमियों का मूल्यांकन करके भावी वर्ष के लिये रणनीति बनानी चाहिए। जिससे कि गलतियों और कमियों को सुधारकर अवसरों में बदला जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में जिस प्रकार से अनेक चुनौतियों का सामना किया, उसी प्रकार भावी वर्ष में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहा जाए तो साल 2026 में नरेंद्र मोदी को अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा और आने वाला वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा व पीएम मोदी के लिये बेहद अहम है। 2026 में देश के 4 राज्यों- असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश- पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में भाजपा के सामने केवल प्रचार का ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की भी चुनौती होगी। इसी क्रम में (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए वर्ष में मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से फर्जी, दोहरे या मृत मतदाताओं के नाम हटाकर वास्तविक और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद को मजबूत करता है। इन पाँच चुनावी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति अलग-अलग है। असम में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि पुडुचेरी में गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ है। इन दोनों स्थानों पर सत्ता को बनाए रखना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ भाजपा अपने संगठन का विस्तार कर राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल भाजपा की रणनीति का प्रमुख केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पक्ष मतदान और जागरूक मतदाता पर जोर देना पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है।

असम और पश्चिम बंगाल में लंबे समय से यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए कथित रूप से मतदाता सूची में शामिल होकर वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह न केवल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके तहत मतदाता सूचियों की गहराई से जांच की जा रही है। सरकार का तर्क है कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में आवश्यक है, जहाँ अवैध घुसपैठ की समस्या को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कुछ घुसपैठियों ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज बनवा लिए हैं, जिसके कारण वे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में ऐसे मतदाताओं का लाभ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, जबकि असम में इसका प्रभाव विपक्षी दलों की स्थिति को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है। सरकार का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य किसी समुदाय या राज्य को निशाना बनाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है, ताकि केवल पात्र और वैध नागरिक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सकता है। जहाँ तक दो दक्षिणी राज्यों-केरल और तमिलनाडु का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि केवल पाने के अवसर ही हैं। यदि भाजपा इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है, भले ही वह सरकार बनाने की स्थिति में न पहुँचे, तब भी यह पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा प्रदर्शन न केवल संगठनात्मक मजबूती को दर्शाएगा, बल्कि भविष्य में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को विस्तार देने की ठोस आधारशिला भी तैयार करेगा। स्पष्ट है कि यदि मोदी सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और प्रभावी संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित करती है, तो आगामी चुनावों में भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इन सभी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता और असफलता सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को प्रभावित करेगी।

मोदी सरकार ने बीते वर्षों में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित किया है, जिनका सीधा लाभ आम जनमानस तक पहुँचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना,

उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, मुफ्त राशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुँच को मजबूत किया है। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अनेक नई पहलें की गई हैं तथा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आरंभ और विस्तार दिया गया है। इन पहलों का उद्देश्य देश के समग्र विकास को गति देना और अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक तक विकास की पहुँच सुनिश्चित करना है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन योजनाओं को केवल घोषणा तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से उनकी तार्किक परिणति तक पहुँचाए और ठोस, सकारात्मक परिणाम सामने लाए। वर्ष 2025 में मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए बीते वर्षों में लागू हुयी योजनाओं- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा हरित ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मिशन जैसी योजनाओं को गति देने का कार्य किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

साथ ही, मोदी सरकार के समक्ष यह भी चुनौती है कि शासन व्यवस्था को सभी स्तरों पर अधिक कुशल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनाया जाए। इस दिशा में डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ई-गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाएँ शासन में विश्वास को मजबूत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इन सुधारों को लेकर निरंतर प्रयासरत रहे हैं और उनका स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि विकास का लाभ केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में दिखाई दे। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और परिणामोन्मुख शासन ही विकसित भारत की नींव को मजबूत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, देश में मोदी सरकार को ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग गरीब एवं मध्यम वर्ग के श्रमिकों के शोषण का माध्यम बनती जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों से कथित रूप से निरंतर वसूली की जाती है, जिसमें कई बार सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त बताए जाते हैं। यह स्थिति न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि श्रम की गरिमा और रोजगार की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। ऐसे में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाने अथवा उसे कठोर नियमों और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था के तहत लाने की ठोस पहल करनी चाहिए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि श्रम नीतियों में सुधार कर स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा।

स्पष्ट है कि नया वर्ष केवल उत्सव या कैलेंडर परिवर्तन का प्रतीक नहीं, बल्कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र-तीनों के लिए आत्ममंथन, मूल्यांकन और नए संकल्प लेने का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ उपलब्धियों के साथ-साथ अनेक राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी सामने हैं। ऐसे में सरकार के लिए आवश्यक है कि वह बीते अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य की दिशा को स्पष्ट और सुदृढ़ बनाए। यदि मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया, मतदाता जागरूकता, राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती तथा सुशासन की भावना के साथ आगे बढ़ती है, तो आने वाला वर्ष लोकतंत्र को और अधिक सशक्त करने वाला सिद्ध हो सकता है। साथ ही, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि, जवाबदेह प्रशासन और नागरिक-केंद्रित नीतियों के माध्यम से सरकार न केवल चुनौतियों का समाधान कर सकती है, बल्कि उन्हें अवसरों में भी बदल सकती है। इस प्रकार नया वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए स्वयं को परखने, नीतियों को धरातल पर उतारने और राष्ट्र को विकास, स्थिरता तथा विश्वास के नए पथ पर आगे ले जाने का अवसर है। यदि यह संतुलन साधा जाता है, तो आने वाला वर्ष न केवल भाजपा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रगति और सशक्त लोकतंत्र का नया अध्याय साबित हो सकता है। वर्ष 2026 में मोदी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ बेहतर लैंगिक संवेदनशीलता भी सुनिश्चित करनी होगी। कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिये तहेदिल से और एकाग्रचित होकर प्रयास करना होगा, जो कि उनके हर प्रयास में दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये वर्ष 2026 में अनेक उपलब्धियाँ गढ़ने का अवसर है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्पूर्ण देश का नागरिक एक सशक्त, एकजुट एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लें तो देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।

कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार का बड़ा फैसला

15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी करा सकेंगे निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज

प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि अब प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेसवार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

अनादि शुक्ल

फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित), माध्यमिक शिक्षा परिषद व संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं

- बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अधीन संचालित अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित), शिक्षणेत्तर कर्मियों व उनके आश्रितों को मिलेगा इसका लाभ
- आयुष्मान की तर्ज पर करा सकेंगे कैशलेस इलाज, स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा योजना का लाभ

सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को आईपीडी (अंतःरोगी विभाग) इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उनके आश्रित भी उठा सकेंगे। प्रेसवार्ता में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

इसी तरह, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/अंशकालिक शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा।

प्रेसवार्ता में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना से बेसिक शिक्षा परिषद के 11.95 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार की इस पहल से प्रति कर्मी करीब 3000 रुपये सालाना प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च अनुमानित है।

कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ साचीज से जुड़े निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से जो लोग केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

लोकतंत्र की आत्मा हैं न्याय, समता व बंधुता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में बुधवार को तीन दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है। संविधान के तीन शब्द (न्याय, समता और बंधुता) भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय कैसे प्राप्त होना है, इसका कानून विधायिका के मंच पर तैयार होता है। समतामूलक समाज की स्थापना में सरकार की योजनाएं योगदान दे सकें, उसकी कार्ययोजना का स्थल भी विधायिका का मंच बनता है। विधायिका बंधुता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां सहमति व असहमति के बीच भी संवाद के माध्यम से समन्वय होता है।

इंद्रेश शर्मा

सीएम योगी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है और यह दुनिया के लिए प्रेरणा है। सदन में जनप्रतिनिधि के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज मजबूती से सुनी जा सकती है और संसद इसकी प्रेरणा का केंद्रबिंदु है। उसके माध्यम से देश में योजनाएं बनती हैं। पांच बार लोकसभा सदस्य रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में रहकर सीखा कि सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विधान सभा-विधान परिषद केवल संसद के नियमों-परिनियमों का अवलोकन-प्रशिक्षण ले ले तो उसे अपने सदन संचालन में काफी आसानी होगी।

सीएम ने कहा कि सतीश महाना ने 2022 में विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला तो मैंने उनसे कहा कि प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन सवा घंटे के प्रश्नकाल में केवल दो-तीन सदस्य ही बोल पाते हैं। क्या हम भी इसे संसद की तर्ज पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर उन्होंने तत्काल नियमावली में परिवर्तन किया। अब सवा घंटे में 20 तारांकित प्रश्न और हर प्रश्न के साथ दो-तीन अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले मंत्रीगण, दोनों पूरी तैयारी के साथ आते हैं। सदन में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता दिखती है। संसद हमारे लिए प्रेरणा बनी। हमारे पास सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में संसद है। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो संसद ही उसका आधार बनती है, उसके प्रति श्रद्धा हर भारतवासी का दायित्व है।

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य 'भारत लोकतंत्र की जननी है' का जिक्र किया, फिर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि ग्राम स्वराज

की परिकल्पना को गांवों ने साकार किया। देश में रूपरंग, खानपान, वेशभूषा अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा भारत एक भाव-एक भंगिमा के साथ बोलता और सोचता है। उसकी आस्था एक होती है। संसद उस आस्था को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। संसद को आदर्श के रूप में बढ़ाएंगे तो विधायिका और मजबूत-सशक्त होगी।

'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' पर 24 घंटे चली चर्चा के सहभागी बने 300 सदस्य

सीएम योगी ने सम्मेलन में पारित हुए छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अभिनंदनीय बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव में आगामी 25 वर्ष की कार्ययोजना बनाने को कहा। 'विजन 2047- विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। सीएम ने कहा कि 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' पर सत्तापक्ष व विपक्ष के 300 से अधिक सदस्य 24 घंटे तक चलने वाली चर्चा के सहभागी बने। चर्चा का शुभारंभ करने के बाद मैं कुछ देर बैठा रहा, फिर अन्य प्रशासकीय कार्यों व बैठकों के लिए जाना पड़ा। रात 11 बजे मैं फिर सदन में आया तो भी यहां बोलने की होड़ दिखी। बहुत अच्छे सुझाव आए। हर व्यक्ति के अनुभव का लाभ अत्यंत प्रभावी होता है। विधानसभा-परिषद में लोगों ने विकास के बारे में मुद्दों को रखा और विकसित भारत के लिए अपनी जिम्मेदारी का भी जिक्र किया। विकसित भारत केवल भारत सरकार, प्रधानमंत्री का ही कार्य नहीं है, हम भी कैसे इस अभियान के सारथी-सिपाही बन सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए, प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को सार्थक गति प्रदान की है।

सीएम ने 30 बैठकों के प्रस्ताव का किया स्वागत

सीएम ने कहा कि यूपी में सदन की कार्यवाही की प्रशंसा की। कहा, यहां कार्यवाही अत्यंत सुगमता से चलती है। सीएम ने वर्ष में कम से कम 30 बैठकों का प्रस्ताव पारित किए जाने को भी सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं, बल्कि नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के लिए भी प्रेरणा है। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि विकास की धुरी बनते हैं। तकनीक के इस युग में हम खुद को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब सरकार के सामने यह बात आई कि ई-विधान होना है तो हमने कहा कि तत्काल इसे लागू कीजिए। आज यूपी की विधानसभा-परिषद, कैबिनेट और बजट भी पेपरलेस है। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी तकनीक से अपडेट हों, उनके उचित प्रशिक्षण समेत सभी प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सीएम ने कहा कि यूपी विधानसभा ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा-परिचर्चा चलाती है। स्थायी विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) पर भी यहां लगातार 37-38 घंटे चर्चा हुई। उसके लक्ष्य निर्धारित हुए। मंत्रिमंडल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर कमेटी गठित हुई, जो इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। 26 नवंबर, संविधान दिवस पर मौलिक अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों को भी हमने विधानसभा-परिषद में अनवरत चर्चा का विषय बनाया। हम विधायकों से कहते हैं यह चर्चा सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे ब्लॉक, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों के स्तर तक विस्तारित करिए।

'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट में जनता से सुझाव लिए। हमारी विधानसभा-परिषद में लगभग 500 जनप्रतिनिधि हैं। इनके साथ ही यूपी के सेवानिवृत मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों समेत समाज के अन्य तबकों से जुड़े 500 लोगों की कार्यशाला की गई।

उन्हें सेक्टर दिए, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए। सबसे कहा गया कि हर किसी को तीन-तीन संस्थाओं में जाकर युवाओं, किसानों, महिला स्वयंसेवी समूहों समेत विभिन्न तबकों को इस मुद्दे से जोड़कर चर्चा करनी है। 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के लिए पोर्टल पर 98 लाख लोगों के सुझाव आए। एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हम उसे फाइनल रूप दे रहे हैं। अलग-अलग सेक्टर में आए सुझावों को विजन डाक्यूमेंट का हिस्सा बनाएंगे। उस विजन डॉक्यूमेंट को लांच करेंगे। इससे हमारी कार्ययोजना के बेहतरीन परिणाम भी आएंगे।

सीएम योगी ने कहा कि पीठ और सरकार का अप्रोच प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता। पीठ ने विपक्ष को अधिक मौका दे दिया तो सरकार रिएक्टिव नहीं होती। पीठ पक्ष-विपक्ष में संतुलन बनाती है। सीएम ने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जहां भी ऐसे सम्मेलन होते हैं, दोनों लोग जाते हैं। वे केवल सदन की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहते। सीएम ने ऐसे सम्मेलनों को 'सीखो-सिखाओ' का मंच बताया।

समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के अलावा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए अतिथिगण मौजूद रहे।

पुलिस पर पथराव की सजा है बुलडोजर नीति

उत्तर प्रदेश में ऐसे अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी करना अब आसान नहीं रहा है। दरअसल पत्थरबाजों को समझ में आ गया है योगी सरकार उनके अवैध घरों–व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलवाए बिना नहीं मानेगी। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में अवैध निमार्णों को सील किया है।

पुलिस का दायित्व है कानून–व्यवस्था बनाए रखना और कानूनों की पालना कराना। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी निभाने के दौरान यदि पुलिसकर्मियों पर हमला हो तो मानना चाहिए कि देश का एक तबका कानून और अदालतों पर भरोसा नहीं रखता है। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान यही हुआ। विपक्षी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अब चुनावी रोटियां सेकने में लगे हुए है। अल्पसंख्यक वोट की राजनीति के कारण ऐसे हालात पैदा होते हैं। दिल्ली महानगर निगम ने हाईकोर्ट के निदेर्शों की पालना में तुर्कमान गेट के पास फैज–ए–इलाही दरगाह के बाहर अतिक्रमण हटाने गए दस्ते और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया

चरण सिंह

गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

यह पहला मौका नहीं है जब अल्पसंख्यक इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और कार्मिकों को पथराव का सामना करना पड़ा हो। इस वर्ष के शुरूआत में ही देश में कई स्थानों पर अल्पसंख्यक इलाकों में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रशासन पर सुनियोजित तरीके से हमले किए गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल कर पत्थरबाजों के अवैध अतिक्रमण ढहाए। जयपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर चौमूं बस स्टैंड के पास स्थित कलंदरी मस्जिद के सामने लंबे समय से पत्थर पड़े हुए थे। इसके अलावा यहां रेलिंग बनाई गई थी, जो कथित तौर पर अवैध थी। 25 दिसंबर 2025 की रात मस्जिद कमेटी और नगर निगम के बीच इन रेलिंग और पत्थरों को हटाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद पुलिस ने रेलिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इससे भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल भी

हुए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू-गैस का छिड़काव और लाठीचार्ज कर स्थिति को संभाला था। इसके बाद अतिक्रमण वाली जगहों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई में 25 मकानों में बनी करीब 40 दुकानों के बाहर तोड़फोड़ की गई है तीन कंपलेक्स को सीज किया गया है।

उत्तर प्रदेश में ऐसे अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी करना अब आसान नहीं रहा है। दरअसल पत्थरबाजों को समझ में आ गया है योगी सरकार उनके अवैध घरों–व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलवाए बिना नहीं मानेगी। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में अवैध निमार्णों को सील किया है। प्राधिकरण ने गोमती नगर विस्तार और चिनहट इलाके में अभियान चलाया है, जिसमें 4 अवैध निर्माण को सील किया गया है। वहीं, दुबग्गा इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। यहां 85 बीघा क्षेत्रफल में 7 अवैध प्लाटिंग की जा रही थीं, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है।

पत्थरबाज अतिक्रमी कानून हाथ में लेने पर उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त रवैया संभल में देख चुके हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अदालत के आदेश पर मस्जिद के आसपास बड़े पैमाने पर बिजली चोरी और अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। जिसमें अवैध कनेक्शन काटे गए और कब्जे हटाए गए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। करीब दर्जनभर अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल या किसी अन्य जिले में किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। संभल का एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाना चाहिए।

इसी तरह प्रयागराज हिंसा के बाद, मुख्य आरोपी जावेद अहमद के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नमाज के बाद भड़की हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के घर पर रविवार दोपहर बुलडोजर चलाया गया। जावेद के दो मंजिला आलीशान मकान पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। सपा नेता आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय का उर्दू गेट 9 मार्च 2019 को ध्वस्त कर दिया गया था। आजम खान ने सरकारी जमीन पर मुख्य सड़क का अतिक्रमण करते हुए गेट बनवाया था। गेट के निर्माण में लगभग 40 लाख रुपये खर्च हुए थे, जिसे भाजपा के सत्ता में आने के बाद ध्वस्त कर दिया गया। लखनऊ के अकबर नगर में विध्वंस अभियान के दौरान 1,200 से अधिक अवैध ढाँचे ध्वस्त किए गए। कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार परियोजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ के अकबर नगर में अब तक 1,200 से अधिक अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन राज्यों में भाजपा का शासन है, वहां पत्थरबाजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। इसके विपरीत विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में अलबत्ता तो ऐसे अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए ही नहीं गए। यदि चलाए भी गए तो पत्थरबाजों के प्रति नरम रवैया अपनाया गया। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। यहां पर भी पत्थरबाजों की इमारतों पर बुलडोजर चला कर सरकार ने संदेश दिया कि कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं है। हरियाणा के नुंह में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद 600 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। पूरे हरियाणा में करीब 104 एफआईआर दर्ज की गई। करीब 216 गिरफ्तारियां हुई।

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने पत्थरबाजों को नहीं बख्शा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव करने की घटना सामने आई थी। भीड़ को पथराव के लिए उकसाने वाले हाजी शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के एक समूह ने गांधीनगर शहर से 38 किमी दूर बहियाल गांव में एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कई दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पथराव किया। पुलिस ने गांव में हुई झड़प और दंगे के लिए लगभग 60 लोगों को हिरासत में लिया था। गांधी नगर में गरबा पर पथराव करने वालों के 186 अवैध इमारत जमीदोंज कर दी गई। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 और 2023 में भारत में लगभग 1.5 लाख घरों (1,53,820) को गिराया गया, जिससे 7.4 लाख से ज्यादा लोग बेदखल हुए। यह आंकड़े 2022 (46,371 घर) और 2023 (107,449 घर) के डेटा पर आधारित हैं और कई कारणों जैसे अवैध निर्माण, शहरी विकास और अन्य प्रशासनिक वजहों से ये घर ध्वस्त हुए। ये घर बुलडोजर कार्रवाई, अवैध निर्माण, शहरी नियोजन, और अन्य प्रशासनिक निर्णयों के कारण गिराए गए। 'भारत में बुल्डोजर अन्याय' और 'भारत के बुल्डोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी' नाम से दो रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल जारी की। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अप्रैल और जून 2022 के बीच लगभग 128 संपत्तियों पर बुल्डोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई।रिपोर्ट में बताया गया है कि असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली वो पांच राज्य हैं, जहां धार्मिक हिंसा और प्रदर्शनों के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सरकार की भेदभावपूर्ण नीति देखने को मिली है और यहां सजा के तौर पर संपत्ति की तोड़फोड़ की गई है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि किस तरह अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रशासनिक दस्ते पर पथराव किए। हिंसा भड़काने के प्रयास किए गए। यह निश्चित है कि देश में ऐसे मामलों में कार्रवाई को जब तक राजनीतिक चश्मे से वोट बैंक के कारण देखा जाता रहेगा, पत्थबरबाजों के हौसले बुलंद रहेंगे।

महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर नेता रहे अजित पवार की राजनीतिक विरासत का कौन बनेगा उत्तराधिकारी?

हम आपको बता दें कि अजित पवार अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार, जो राज्यसभा सांसद हैं और दो पुत्र पार्थ व जय को छोड़ गए हैं। सुनेत्रा पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनाव लड़ा था, जहां उनका मुकाबला अपनी ननद सुप्रिया सुले से हुआ था।

महाराष्ट्र की राजनीति आज सुबह एक भयानक सदमे से हिल गई जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का चार्टर्ड विमान बारामती जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग की लपटों में समा गया। जिला परिषद चुनाव के लिए रैली में शामिल होने जा रहे अजित पवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब सवाल यह है कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? सवाल यह भी है कि अजित पवार के निधन के बाद क्या अब उनकी पार्टी और उनके विधायक एकजुट रह पाएंगे? सवाल यह भी है कि यदि अजित पवार की पत्नी या बेटे ने एनसीपी की कमान संभाली तो क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता उसी तरह उनके आदेश का पालन

हरेन्द्र शर्मा

करेंगे जैसा कि वह अजित पवार के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए करते थे?

हम आपको बता दें कि अजित पवार अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार, जो राज्यसभा सांसद हैं और दो पुत्र पार्थ व जय को छोड़ गए हैं। सुनेत्रा पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनाव लड़ा था, जहां उनका मुकाबला अपनी ननद सुप्रिया सुले से हुआ था। यह मुकाबला इसलिए भी राष्ट्रीय चर्चा में रहा क्योंकि यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन और पवार परिवार की अंदरूनी दरार के तुरंत बाद हुआ था। जीत सुप्रिया सुले की हुई थी और बाद में राज्यसभा चुनाव जीत कर सुनेत्रा पवार भी संसद पहुँचीं। भले सुनेत्रा अजित पवार की स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी मानी जा रही हों लेकिन चुनावी राजनीति का अनुभव उनका बेहद कम है।

देखा जाये तो अजित पवार का निधन ऐसे समय हुआ है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से ही संक्रमण के दौर से गुजर रही है। हालिया निकाय चुनावों में एनसीपी के दोनों गुटों को निराशा ही हाथ लगी थी। हम आपको याद दिला दें कि जुलाई

2023 में एनसीपी टूट चुकी थी और चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को आधिकारिक एनसीपी और घड़ी चुनाव चिन्ह सौंपा था। वह छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे और वर्तमान महायुति सरकार में भी यही पद संभाल रहे थे। उनके जाने से सरकार के भीतर भी समीकरण बदलने की आशंका है। हम आपको बता दें कि एनसीपी के 41 विधायक हैं।

हाल के महीनों में यह संकेत भी मिलने लगे थे कि अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच रिश्तों में नरमी आ रही है। पुणे और पिंपरी चिंचवड के नगर निगम चुनावों को दोनों गुटों ने साथ मिलकर लड़ा था। साथ ही आगामी निकाय चुनावों के लिए भी तालमेल घोषित किया गया था। ऐसे में अजित पवार की अचानक मौत ने संभावित मेल मिलाप की प्रक्रिया को अधर में लटका दिया है।

देखा जाये तो अजित पवार केवल उपमुख्यमंत्री नहीं थे, वह सत्ता की धुरी थे, वह धुरी जो पवार परिवार के अलग अलग धड़ों, ग्रामीण महाराष्ट्र की राजनीति और दिल्ली के समीकरणों को एक साथ थामे हुए थी। अब सवाल यह नहीं कि शोक कितना गहरा है, सवाल यह है कि इस शून्य को कौन भरेगा और किस कीमत पर।

एनसीपी आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां नेतृत्व का संकट केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि वंशानुगत भी है। एक तरफ सुनेत्रा पवार हैं, जिनके नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अजित पवार की विरासत संभाल सकती हैं। दूसरी तरफ पार्थ पवार हैं, जिन्हें उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, भले ही उनका राजनीतिक अनुभव सीमित हो और उनके साथ जुड़े हालिया विवादों ने पार्टी को रक्षात्मक बना दिया हो। वहीं जय पवार फिलहाल राजनीति से दूर हैं, लेकिन पवार परिवार में दूरी स्थायी नहीं होती।

दूसरी ओर शरद पवार खेमे में रोहित पवार को आगे बढ़ाया जा रहा है। युवा, आक्रामक और निष्ठावान रोहित पवार राज्य की राजनीति में अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पार्थ और रोहित के बीच वैचारिक और व्यक्तिगत टकराव किसी भी संभावित एकीकरण को बेहद कठिन बना देता है। ऊपर से 2024 चुनाव में सुनेत्रा को बाहरी कहने वाली टिप्पणी ने जो जख्म दिए, वे अभी भरे नहीं हैं।

अजित पवार वह नेता थे जो सत्ता में रहने के लिए सत्ता को साधना जानते थे। उन्होंने भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस सभी के साथ सरकारें चलाईं और हर बार खुद को अपरिहार्य साबित किया। वह जनता से कहते थे कि सत्ता सेवा का साधन है और उसी तर्क से अपने राजनीतिक मोड़ बदलते रहे। यह लचीलापन ही उनकी ताकत था और यही अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी कमी बन गया है।

अब एनसीपी के सामने तीन रास्ते हैं। पहला, दोनों गुटों का विलय, जो भावनात्मक रूप से आकर्षक है लेकिन व्यवहारिक रूप से विस्फोटक। दूसरा, अजित पवार गुट का अलग अस्तित्व, जहां अनुभवहीन नेतृत्व को विधायकों को जोड़े रखने की अग्निपरीक्षा देनी होगी। तीसरा, शरद पवार का सक्रिय राजनीति से हटने का फैसला टलना, ताकि वे इस उथल पुथल में संतुलन बनाए रख सकें।

महाराष्ट्र की राजनीति में पवार नाम सिर्फ एक सरनेम नहीं, एक ब्रांड है। अजित पवार उस ब्रांड के सबसे तेज धार वाले औजार थे। उनके बिना यह ब्रांड बिखर भी सकता है और नए सिरे से गढ़ा भी जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में एनसीपी के भीतर सत्ता संघर्ष और तेज होगा और विरासत की यह जंग महाराष्ट्र की राजनीति को और आक्रामक बनाएगी।

बहरहाल, यह सही है कि शोक के इस क्षण में संयम की बातें होंगी, लेकिन राजनीति शून्य नहीं सहती। अजित पवार की चिता की आग ठंडी होने से पहले उत्तराधिकार की आग भड़क चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस आग में कौन राख बनेगा और कौन सत्ता की भट्टी में खुद को नया नेता गढ़ पाएगा।

'एक भारत, एक कानून' की नीतिगत कसौटी के सियासी निहितार्थ

यह ठीक है कि इस राह में कई संरचनात्मक बाधाएं हैं, लेकिन राष्ट्र के दूरगामी भविष्य के लिए इन कपोलकल्पित बाधाओं, वैधानिक जटिलताओं से निबटना भी तो सकारात्मक और आशावादी नेतृत्व की पहचान होती है। खासकर मोदी हैं तो मुमकिन है, वाली सोच यहां भी चरितार्थ की जा सकती है।

विभिन्न तरह के पारस्परिक विरोधाभासों से जूझ रहे भारतीय गणतंत्र के लिए 'एक भारत, एक कानून' की अवधारणा बदलते वक्त की मांग है। इसलिए इसको सरजमीं पर उतरना बेहद जरूरी है। सवाल है कि जब एक मतदाता, एक वोट का विधान सफल हो सकता है तो फिर एक भारत, एक कानून का विधान क्यों नहीं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसी सकारात्मक कोशिशें अंततोगत्वा समतामूलक समाज की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं।

लिहाजा यदि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और अन्यान्य विविधताओं को बनाए रखने वाले नानाविध प्रावधानों से 'एक देश, एक कानून' की पावन और समदर्शी सोच टकराती है तो ऐसे किसी भी टकराव को नजरअंदाज कीजिए और एक समान

रवि जैन

नागरिक संहिता (UCC) या एकसमान कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक यथार्थपरक व्यवहारिक कदम उठाइए। इससे दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सवर्ण जैसे निरर्थक भेद भी मिटेंगे और राष्ट्र को अप्रत्याशित मजबूती मिलेगी।

यह ठीक है कि इस राह में कई संरचनात्मक बाधाएं हैं, लेकिन राष्ट्र के दूरगामी भविष्य के लिए इन कपोलकल्पित बाधाओं, वैधानिक जटिलताओं से निबटना भी तो सकारात्मक और आशावादी नेतृत्व की पहचान होती है। खासकर मोदी हैं तो मुमकिन है, वाली सोच यहां भी चरितार्थ की जा सकती है। योगी हैं तो यकीन भी किया जा सकता है। शाह हैं तो चिल्लपों भी नहीं मचेगा, ऐसा जनविश्वास है।

जहां तक संघीय ढांचे की चुनौतियों की बात है तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का त्रिपक्षीय विभाजन (केंद्र, राज्य, समवर्ती) एक देश, एक कानून की राह का एक बड़ा रोड़ा समझा जाता है। उदाहरणतया पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे विषय राज्य सूची में हैं, जिनमें केंद्र का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं होगा बिना संशोधन के। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 246 इस विभाजन को मजबूत बनाता है, जो एकसमान कानून लागू करने में राज्यों की सहमति या संविधान संशोधन की मांग करता है।

वहीं, मौलिक अधिकारों का टकराव भी संभाव्य है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जो व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को संरक्षण प्रदान करते हैं। वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुच्छेद 44 के नीति-निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है और मौलिक अधिकारों से टकरा सकता है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लागू करने पर जोर दिया है (जैसे शाह बानो मामले में), लेकिन संघीय विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस राह की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

वहीं, व्यावहारिक और न्यायिक अड़चनों की बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका (अनुच्छेद 214) होने के बावजूद, राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता और लंबित मामलों (5 करोड़ से अधिक) की भारी संख्या एकसमान कानून के कार्यान्वयन को जटिल बनाती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति जरूरी हो सकती है, जो राजनीतिक मतभेदों से अवरुद्ध रहती है।

जहां तक संभावित प्रभाव की बात है तो ये अड़चनें वास्तव में संविधान की विविधता-समर्थक भावना को दशार्ती हैं, जो एकता के साथ बहुलवाद को संतुलित रखती हैं। हालांकि, डिजिटल युग में एकसमान कानून आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बिना व्यापक सहमति के यह संघीय तनाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार और उसकी राज्य सरकारों को इस बाबत आम सहमति तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक भारत, एक कानून में ही न केवल देश, बल्कि दुनिया का भी हित निहित, अंतर्निहित है।

देखा जाए तो समान नागरिक संहिता, भारतीय संविधान की मौलिक व्यवस्था पर ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, खासकर समानता के अधिकार को मजबूत करके, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में यह टकराव पैदा कर सकता है। हालांकि, धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक कमजोरी का प्रतीक है। यह ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह नीति-निर्देशक सिद्धांत राज्य को एकसमान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करने को कहता है, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ता है। जहां तक समानता अधिकारों पर प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 14 (विधि के

समक्ष समानता) और 15 (भेदभाव निषेध) को मजबूत बनाएगा, क्योंकि यह धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसी के द्वारा तीन तलाक, असमान उत्तराधिकार जैसे मुद्दों का सम्यक समाधान हो सकता है, जो महिलाओं के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) को प्रभावित करते हैं। हालांकि, यदि गलत तरीके से लागू हुआ तो यह अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव का आरोप लगा सकता है।

जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव की बात है तो अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता और प्रबंधन का अधिकार देते हैं, जो यूसीसी से टकरा सकता है क्योंकि व्यक्तिगत कानून सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो और सारला मुद्गल मामलों में यूसीसी की आवश्यकता बताई, लेकिन इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न मानते हुए संतुलित किया। फिर भी जनजातीय रीति-रिवाजों वाली समुदायों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।

जहां तक अन्य मौलिक प्रावधानों पर यूसीसी के प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 21 को सशक्त बनाएगा, क्योंकि यूसीसी पितृसत्तात्मक प्रथाओं को चुनौती देगा और न्याय प्रक्रिया को सरल करेगा। लेकिन समवर्ती सूची के विषय होने से राज्य स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, जो संघीय ढांचे से जुड़ी मौलिक भावना को कमजोर करेगी। कुल मिलाकर, यूसीसी मौलिक अधिकारों को आधुनिक संदर्भ दे सकता है यदि सहमति-आधारित हो तो।

यही वजह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्पष्ट निर्देश देने से इनकार किया है, बल्कि इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना है। भले ही कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में यूसीसी के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन कार्यपालिका को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। जहां तक कोर्ट के रुख की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में यूसीसी लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि यह विधायी मामला है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने मार्च 2023 में छह याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि यूसीसी संसद बनाएगी। इससे पहले आये निम्नलिखित प्रमुख फैसले में भी यूसीसी की चर्चा है। शाह बानो (1985), सरला मुदगल (1995), और जॉन वल्लामट्टम (1997) जैसे मामलों में कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन निर्देश नहीं दिए। इसी प्रकार जनवरी 2023 में उत्तराखंड यूसीसी समिति को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज हुईं। जहां तक वर्तमान स्थिति की बात है तो जनवरी 2026 तक कोई नया निर्देश नहीं आया; क्योंकि कोर्ट यूसीसी को अनुच्छेद 44 के नीति-निर्देशक सिद्धांत के रूप में देखता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन पर जोर देता है। यही वजह है कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने 2024 में राज्य-स्तरीय यूसीसी लागू किया। समझा जा रहा है कि धीरे धीरे मोदी-शाह इसे पूरे देश में लागू करेंगे।

हालांकि इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सभी जनहितकारी मामलों में यदि एक देश, एक कानून जैसे अग्रगामी प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है तो विगत 100 सालों से अनवरत रूप से जारी फूट डालो, शासन करो की नीति का जड़मूल से खात्मा हो जाएगा। यद्यपि मुट्ठी भर चतुर सुजान विदेशी टुकड़े पर विरोध अवश्य करेंगे लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटवाकर एक विधान, एक निशान की राष्ट्रीय नीति लागू करवा सकते हैं तो उनके लिए एक देश, एक कानून को मूर्त रूप देना-दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि इस मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस की नीति साफ और नीयत स्पष्ट हो।

गणतंत्र के 76 वर्ष: संविधान की आत्मा और लोकतंत्र का यथार्थ

सही मायनों में गणतंत्र की मूल भावना को हमने आज तक समझा ही नहीं है। 'गणतंत्र' का अर्थ है शासन तंत्र में जनता की भागीदारी। हालांकि हम कह सकते हैं कि शासन तंत्र में जनता को पूर्ण भागीदारी मिली है किन्तु क्या यह वाकई पूर्ण सत्य है? देश का संविधान लागू होने के इन 76 वर्षों में भी क्या वास्तव में शासन तंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है?

प्रतिवर्ष की भांति एक बार फिर गणतंत्र दिवस हमारी राष्ट्रीय चेतना के द्वार पर उपस्थित है। यह दिन प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत ने औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर अपने ही द्वारा निर्मित संविधान को आत्मसात किया था और स्वयं को प्रभुता संपन्न, सार्वभौमिक, प्रजातंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। यह केवल एक संवैधानिक घटना नहीं थी बल्कि भारत की ऐतिहासिक चेतना, संघर्षशील आत्मा और स्वशासन की आकांक्षा का औपचारिक उद्घोष था। किन्तु इस ऐतिहासिक गौरव के समानांतर एक कड़वा

कपिल शर्मा

यथार्थ भी हमारे सामने खड़ा है। समय के साथ गणतंत्र दिवस का महान उद्देश्य धीरे-धीरे औपचारिकताओं और रस्म अदायगी तक सीमित होता चला गया है। जिस भावना के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई थी, उसका मूल आशय था कि प्रत्येक नागरिक इस दिन संविधान की गरिमा की रक्षा, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा और देशसेवा के प्रति अपने दायित्वों को न केवल दोहराए बल्कि उन्हें अपने आचरण में भी उतारे। विडंबना यह है कि आज हम इस गौरवपूर्ण अवसर पर संवैधानिक मूल्यों के प्रति संकल्प लेने के बजाय मात्र उन्हें स्मरण कर आत्मसंतोष कर लेते हैं। झंडारोहण, परेड और भाषणों के बाद जैसे हमारे कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस यदि केवल उत्सव बनकर रह जाए और संवैधानिक चेतना व्यवहार में न उतरे तो यह गणतंत्र की आत्मा के साथ अन्याय ही कहा जाएगा।

सही मायनों में गणतंत्र की मूल भावना को हमने

आज तक समझा ही नहीं है। 'गणतंत्र' का अर्थ है शासन तंत्र में जनता की भागीदारी। हालांकि हम कह सकते हैं कि शासन तंत्र में जनता को पूर्ण भागीदारी मिली है किन्तु क्या यह वाकई पूर्ण सत्य है? देश का संविधान लागू होने के इन 76 वर्षों में भी क्या वास्तव में शासन तंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है? जनता को यह तो अधिकार है कि मतदान के जरिये वह अपना जनप्रतिनिधि चुने किन्तु एक बार संसद अथवा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अगले पांच वर्षों तक इन जनप्रतिनिधियों पर उसका क्या कोई अंकुश रह जाता है? वास्तविकता यही है कि इसी प्रावधान का लाभ उठाते हुए राजनीतिक दल देश की जनता का चुनाव के समय महज एक वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं और अपना मतलब निकलने पर जनप्रतिनिधियों पर जनता के दुख-दर्द के बजाय अपने लिए सुख-सुविधाओं का अंबार जुटाने की चिंता सवार हो जाती है और वे इसी कवायद में जुट जाते हैं कि येन-केन-प्रकारेण अगले चुनाव के लिए कैसे करोड़ों रुपयों का इंतजाम किया जाए। अहम सवाल यह है कि जिस राष्ट्र में जनता की भागीदारी चुनाव में सिर्फ वोट डालने और उसके बाद चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण से शर्मसार होकर आंसू बहाने तक ही सीमित रह गई हो, वहां 'गणतंत्र' का भला क्या महत्व रह गया है? खासतौर से ऐसी स्थिति में, जब गरीबी व भुखमरी से त्रस्त करोड़ों लोग चंद रुपयों की खातिर या लाखों लोग महज दो-चार शराब की बोतलों के लिए अपने वोट बेच डालते हों या ईवीएम के दौर में भी कुछ मतदान केन्द्रों पर गुंडागर्दी के बल पर वोट डलवाये जाते हों?

हालांकि इसमें कोई संशय नहीं कि हमें विशुद्ध रूप में एक प्रजातांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक सम्प्रदाय के लोगों के लिए बराबरी के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी की गई है, प्रत्येक नागरिक के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है किन्तु गणतांत्रिक भारत में पिछले 76 वर्षों के हालातों का विवेचन करें तो यही पाते हैं कि हमारे कर्णधार एवं नौकरशाह किस प्रकार संविधान के कुछ प्रावधानों के लचीलेपन का अनावश्यक लाभ उठाकर कदम-कदम पर लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार करते रहे हैं। निसंदेह इससे लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती रही है। संविधान निमार्ताओं ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिन लोगों के कंधों पर संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी, वही इसके प्रावधानों का मखौल उड़ाते नजर आएंगे। ऐसी दयनीय परिस्थितियों को देखकर निश्चित रूप से संविधान निमार्ताओं की आत्मा खून के आंसू रोती होगी।

वक्त-बेवक्त संसद और विधानसभाओं के भीतर होती गुंडागर्दी सरीखी घटनाएं दुनियाभर में हमें शर्मसार करती रही हैं। जिस राष्ट्र में कानून बनाने वाले और देश चलाने वाले लोग ही असभ्य हरकतें करने लगें, वहां अपराधों पर अंकुश लगाने की किससे अपेक्षा की जाए? संसद-विधानसभा सरीखे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिरों में अपराधियों व बाहुबलियों का निर्बाध प्रवेश क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है? चुनाव जीतने के लिए आज हर राजनीतिक दल में ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने, चुनाव जीतने के लिए उनका इस्तेमाल करने के अलावा उन्हें ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाकर अपनी सीटें बढ़ाने के फेर में ऐसे दागी लोगों को लोकतंत्र के मंदिरों में प्रवेश दिलाने की होड़ सी लगी है। संसद और विधानसभाओं में धड़ाधड़ प्रवेश पाते अपराधियों का संख्या बल देखें तो यह 'प्रजातंत्र' या 'गणतंत्र' कम, 'अपराधतंत्र' अधिक लगने लगा है। अदालतें जब भी संसद या विधानसभाओं में अपराधिक तत्वों का प्रवेश रोकने की दिशा में कुछ सार्थक पहल करने की कोशिश करती हैं, तमाम राजनीतिक दल उसे संसद के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक दखलंदाजी करार देते हुए हो-हल्ला मचाने लगते हैं।

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सांसदों-विधायकों की रूचि लगातार कम हो रही है। प्रत्येक संसद सत्र में हंगामा व शोरशराबा करके संसद का बेशकीमती समय नष्ट कर देना जैसे एक परम्परा बन चुकी है। सदन से बहुत से सदस्य लंबे-लंबे समय तक गैरहाजिर रहते हैं। सर्वसम्मति के अभाव में देशहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण बिल लंबे समय तक लटके पड़े रहते हैं लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्ते अथवा अन्य ऐशोआराम की सुविधाएं बढ़ाने की बात आती है तो पूरा सदन एकजुट हो जाता है और ऐसे मामलों में पलक झपकते ही सर्वसम्मति बन जाती है। तब सदन में सदस्यों की उपस्थिति संख्या भी देखते ही बनती है। एक समय था, जब संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक बहस होती थी लेकिन अब हर संसद सत्र हंगामे और शोरशराबे की भेंट चढ़ जाता है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि संसद का एक-एक मिनट बहुमूल्य होता है। संसद के प्रत्येक मिनट के कामकाज पर ढ़ाई लाख रुपये से अधिक खर्च होते हैं अर्थात आठ घंटे की संसद की कार्रवाई पर बारह करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च होते हैं। आए दिन इसी तरह संसद में हंगामे होने, सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करने या सदन की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित होने से देश को कितना आर्थिक नुकसान होता है, इसका अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है। संसद अथवा विधानसभाओं की कार्रवाई पर होने वाला यह भारी-भरकम खर्च जनप्रतिनिधियों की जेबों से नहीं निकलता बल्कि इसका सारा बोझ देश की आम जनता वहन करती है। बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 'गणतंत्र' की जो तस्वीर हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, क्या हम उस पर गर्व कर सकते हैं? गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का सही लाभ तभी है, जब न केवल देश का प्रत्येक नागरिक बल्कि बड़े-बड़े राजनेता और नौकरशाह भी संविधान की गरिमा को समझें और उसके अनुरूप अपने आचरण में पारदर्शिता भी लाएं।

इतिहास का सबसे लंबा अनुत्तरित प्रश्न नेताजी की मौत

ब्रिज पंवार

नेताजी के जीवित रहने को लेकर किए गए विभिन्न दावों में कहा गया कि वे विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए थे बल्कि जीवित बच गए थे और उन्होंने अपने जीवन का बाकी हिस्सा गुप्त रूप से बिताया। ऐसे ही दावों में से एक दावा यह भी था कि विमान दुर्घटना में नेताजी को गंभीर रूप से चोटें लगी थी लेकिन वे जीवित बच गए थे।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दरअसल उनकी मृत्यु के संबंध में कई दशकों से यही दावा किया जाता रहा है कि 18 अगस्त 1945 को सिंगापुर से टोक्यो (जापान) जाते समय ताइवान के पास फामोर्सा में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। नेताजी ने 16 अगस्त 1945 को टोक्यो से ताइपेई के लिए उड़ान भरी थी और जापानी द्वितीय विश्व युद्ध का उनका विमान 18 अगस्त की सुबह ताइपेई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद जापान सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि उस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपेई में विमान दुर्घटना में उनकी मौत की जापान सरकार द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था लेकिन आज भी कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। दरअसल उनके जीवित होने और गुमनामी में जीवन जीने के दावे किए जाते रहे हैं और इस विषय पर कई बार जांच भी हुई है। हालांकि नेताजी के जीवित होने का दावा करने वाले लोगों ने कई बार अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत पेश किए लेकिन उन सबूतों को प्रायः संदिग्ध माना गया है और कहा जाता रहा है कि उनके जीवित होने के दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं।

दरअसल नेताजी का शव कभी नहीं मिला और कुछ अन्य कारणों से भी उनकी मौत के दावों पर आज तक विवाद बरकरार है। उनकी मृत्यु का रहस्य जानने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा पूर्व

में कुछ आयोगों का गठन भी किया जा चुका है और कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच भी गठित की गई किन्तु अभी तक रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले तक में नेताजी के होने संबंधी कई दावे भी पिछले दशकों में पेश हुए किन्तु सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध रही और नेताजी की मौत का रहस्य यथावत बरकरार है।

हालांकि जापान सरकार बहुत पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं और भारत सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व सार्वजनिक की गई नेताजी से संबंधित कुछ गोपनीय फाइलों में मिले एक नोट से तो यह सनसनीखेज खुलासा भी हुआ कि 18 अगस्त 1945 को हुई कथित विमान दुर्घटना के बाद भी नेताजी ने तीन बार 26 दिसम्बर 1945, 1 जनवरी 1946 तथा फरवरी 1946 में रेडियो द्वारा राष्ट्र को सम्बोधित किया था। इस खुलासे के बाद से ही नेताजी की मौत का रहस्य और गहरा गया था।

नेताजी के जीवित रहने को लेकर किए गए विभिन्न दावों में कहा गया कि वे विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए थे बल्कि जीवित बच गए थे और उन्होंने अपने जीवन का बाकी हिस्सा गुप्त रूप से बिताया। ऐसे ही दावों में से एक दावा यह भी था कि विमान दुर्घटना में नेताजी को गंभीर रूप से चोटें लगी थी लेकिन वे जीवित बच गए थे और उन्हें एक जापानी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनका इलाज किया गया और बाद में उन्हें सोवियत संघ ले जाया गया, जहां उन्हें एक गुप्त शिविर में रखा गया। एक अन्य दावा यह भी था कि नेताजी ने विमान दुर्घटना में बचने के लिए अपना रूप बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल ली थी और एक गुप्त जीवन जीने लगे थे। कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि उन्होंने नेताजी को गुप्त रूप से रहने के दौरान देखा है। हालांकि इन तमाम दावों में से किसी का भी कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला लेकिन इन दावों को लेकर सच्चाई जानने को लेकर लोगों में सदैव उत्सुकता रही है। उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए कई बार जांच आयोग भी बैठाए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जांच आयोग

एक अन्य दावा यह भी था कि नेताजी ने विमान दुर्घटना में बचने के लिए अपना रूप बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल ली थी और एक गुप्त जीवन जीने लगे थे।

न्यायमूर्ति ताराचंद की अध्यक्षता में 1956 में बैठाया गया था। ताराचंद आयोग ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। आयोग ने कहा था कि नेताजी के जीवित रहने के दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है लेकिन आयोग के निष्कर्षों को कई लोगों ने चुनौती दी थी, जिनका कहना था कि आयोग ने नेताजी के जीवित रहने के दावों की पर्याप्त जांच नहीं की थी। आज भी दावे के साथ यह कहना मुश्किल है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। हो सकता है कि वे विमान दुर्घटना में मारे गए हों या यह भी हो सकता है कि वे जीवित बच गए हों और उन्होंने अपना जीवन गुप्त रूप से बिताया हो। कुल मिलाकर, उनकी मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है और इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग का वैश्विक फलाफल

देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां नाटो पर दबाव बढ़ा रही हैं, खासकर ग्रीनलैंड विवाद और रक्षा खर्च मांग के माध्यम से। इसके वैश्विक दुष्प्रभाव या असर को समझते हुए ही अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्द्ध में खुद को मजबूत करने के लिए बेनेजुएला सम्प्रभुता तहस नहस कांड कांड जैसा दुस्साहस दिखाया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित ब्लैकमेलिंग वाली कूटनीतिक रणनीति, विशेष रूप से टैरिफ और क्षेत्रीय दावों के माध्यम से, उनके मित्र देश रह रह कर परेशान हो उठते हैं। जबकि अमेरिका के शत्रु देश उनको आंख दिखाकर अपनी मनवाने से भी नहीं चूकते, खासकर चीन, रूस और ईरान जैसे दबंग देश। इससे जहां वैश्विक कूटनीति चौराहे पर खड़ी प्रतीत होती है, वहीं

प्रवीण सिंह कुशवाहा

उनकी ढुलमुल नीति व्यापार को गहराई से प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि यूरोपीय देश, जापान, भारत आदि अंदर से बेचैन हैं। सच कहूं तो राष्ट्रपति ट्रंफ का यह अव्यवहारिक व मतलबपरस्त रुख आर्कटिक सुरक्षा, नाटो एकता और बहुपक्षीय व्यापार नियमों को खुली चुनौती दे रहा है।

सबसे पहले इसी कसौटी पर यूरोप व नाटो देशों से जुड़े ग्रीनलैंड विवाद को समझते हैं, जहां ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की मांग क्या रख दी, उनके इस अटपटी सोच से उनके मित्र भी बौखलाहट दिखाने लगे। जिससे परेशान

अमेरिका ने सहयोगी से विरोधी बन रहे आठ यूरोपीय देशों (डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी आदि) पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो जून 2026 तक 25% हो सकता है। यही वजह है कि यूरोपीय नेता जैसे स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने सहयोग की बजाय संवाद पर जोर देते हुए इसे स्पष्ट ₹ब्लैकमेलर₹ करार दिया। वहीं, नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने ट्रंप से बातचीत की पुष्टि की, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका जताई।

जहां तक चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध की बात को इस ब्लैकमेलिंग वाली कसौटी पर कसें तो प्रतीत होता है कि साल 2025 में ट्रंप द्वारा चीन पर 104% टैरिफ लगाने को चीन (बीजिंग) ने खुलकर ₹ब्लैकमेलिंग₹ बताया और अंत तक लड़ने का वादा किया। चीनी पीएम ली कियांग ने इसे संरक्षणवाद का उदाहरण माना, और प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही। इससे वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी की आशंका बढ़ी, क्योंकि अमेरिका ने 70+ देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए।

वहीं ट्रंफ की ब्लैकमेलिंग वाली कूटनीति का वैश्विक प्रभाव भी साफ दिख रहा है, क्योंकि उनकी इस रणनीति से नाटो जैसे गठबंधनों में दरार डाल पड़ने लगी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के संकेत भी मिलने लगे हैं, क्योंकि 1 फरवरी 2026 की डेडलाइन नजदीक है। यूरोप ने आपात बैठक बुलाई, जबकि भारत जैसे देश भी 26% से 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहे हैं। इससे इनकी बेचैनी समझी जा सकती है। कुल मिलाकर, ट्रंफ की ब्लैकमेलिंग वाली कूटनीति सिर्फ अमेरिका-प्रथम नीति को प्राथमिकता देती है, लेकिन इससे बहुपक्षीय संस्थाओं के कमजोर होते चले जाने की आशंका भी निराधार नहीं है।

देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां नाटो पर दबाव बढ़ा रही हैं, खासकर ग्रीनलैंड विवाद और रक्षा खर्च मांग के माध्यम से। इसके वैश्विक दुष्प्रभाव या असर को समझते हुए ही अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्द्ध में खुद को मजबूत करने के लिए बेनेजुएला सम्प्रभुता तहस नहस कांड कांड जैसा दुस्साहस दिखाया। इससे रूस, चीन, भारत, ईरान की फटी पड़ी पैबंद भी सामने आ गई। यह सबकुछ इसलिए किया गया ताकि 'अमेरिका फर्स्ट' दृष्टिकोण को और अधिक मजबूत किया जा सके। अमेरिका की यह खुली पहल उसके नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन की एकता को दो टूक चुनौती दे रही है, लेकिन कुछ नाटो सदस्यों ने जिस तरह से अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, उससे ट्रंफ का मनोबल बढ़ा है। जहां तक ग्रीनलैंड सम्बन्धी तनाव की बात है तो ट्रंप की ग्रीनलैंड अधिग्रहण जैसी अव्यवहारिक मांग का विरोध होने के बाद अमेरिका ने डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी जैसे नाटो सदस्यों पर भी 10% टैरिफ लगाए, जो 25% तक बढ़ सकते हैं। जबकि यूरोपीय देशों ने आर्कटिक में सैन्य तैनाती बढ़ाई, जबकि ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। इस पर नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने ट्रंफ सेवबातचीत की, लेकिन विशेषज्ञ इसे गठबंधन के ₹सबसे काले घंटे₹ की संभावना मानते हैं।

जहां तक नाटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने सम्बन्धी अमेरिकी दबाव की बात है तो ट्रंप ने सदस्य देशों से जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने की मांग की, जो पहले 2% के वेल्स वादे से दुगुने से भी ऊपर है। उनके दावे के अनुसार, इस दबाव से खर्च बढ़ा, लेकिन यूरोप को अमेरिकी सुरक्षा ₹ब्लैंक चेक₹ बंद करने की चेतावनी दी। इससे यूरोपीय नेता नाराज हैं, जो नाटो विस्तार (जैसे यूक्रेन) रोकने का संकेत भी देता है।

जहां तक ट्रंफ के ब्लैकमेलिंग वाली कूटनीति के संभावित प्रभाव की बात है तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनकी ये नीतियां नाटो में दरार पैदा कर सकती हैं, और ट्रांस-अटलांटिक संबंधों को कमजोर करेंगी।

यही वजह है कि अमेरिकी संसद में नाटो से निकासी के विधेयक आए हैं, हालांकि तत्काल विदड्रॉल नहीं हुआ। कुल मिलाकर, लेन-देन वाली कूटनीति गठबंधन की विश्वसनीयता को खतरे में डाल रही है। जबकि अमेरिकी सोच है कि यूरोप की गफलत में फंसकर रूस और एशिया की चकरघिन्नी में फंसकर चीन से खुली दुश्मनी लेने से बेहतर है कि खुद को पश्चिमी गोलार्द्ध यानी उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के देशों के बीच महफूज रखो और यहां पर यूरोपीय/एशियाई देशों की दाल नहीं गल सके, इस हेतु बेनेजुएला जैसी अप्रत्याशित कार्रवाई करते रहो।

पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू लहूलुहान हो रहे हैं: दुनिया देख रही खामोशी से तमाशा

बांग्लादेश में हालात और भी भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। बीते कुछ ही दिनों में वहां हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। छत्तोग्राम में एक हिंदू किशोरी का शव मिलने की घटना ने समाज को हिला कर रख दिया।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई एक खबर ने पूरे दक्षिण एशिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। एक गरीब हिंदू किसान को केवल इसलिए गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने अपनी जमीन पर झोपड़ी बनाने का साहस कर लिया था। यह हत्या किसी अंधेरी गली में नहीं बल्कि खुले आम ताकत और दहशत के प्रदर्शन के रूप में हुई। मृतक किसान वर्षों से उसी जमीन पर रह रहा था, लेकिन स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने रसूख और हथियार के बल पर कानून को कुचल दिया। इस

संजय बैंसला

निर्मम हत्या के बाद सिंध के कई इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने नारे लगाए, रास्ते जाम किए और इंसाफ की मांग की। यह आक्रोश केवल एक व्यक्ति की हत्या का नहीं बल्कि दशकों से दबे हुए भय और अपमान का विस्फोट था।

उधर, बांग्लादेश में हालात और भी भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। बीते कुछ ही दिनों में वहां हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। छत्तोग्राम में एक हिंदू किशोरी का शव मिलने की घटना ने समाज को हिला कर रख दिया। आशंका है कि उसके साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई। यह कोई एक मामला नहीं है बल्कि कुछ ही दिनों में हिंदुओं की कई हत्याओं की खबरें आई हैं। मंदिरों में तोड़फोड़, घरों में आगजनी, महिलाओं के साथ हिंसा और डर का

माहौल वहां की रोजमर्रा की सच्चाई बनता जा रहा है। भारत ने इन घटनाओं पर कड़ी चिंता जताई है और बांग्लादेश सरकार से त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि पीड़ितों को न सुरक्षा मिल रही है और न न्याय का भरोसा।

पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों से आ रही ये खबरें यह साफ करती हैं कि वहां हिंदू

अल्पसंख्यक होना आज भी एक खतरे के साथ जीने जैसा है। यह केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि देश और समाज दोनों की नैतिक हार है।

देखा जाये तो सिंध के उस किसान की लाश और छत्तोग्राम की उस किशोरी का शव सिर्फ दो खबरें नहीं हैं। वे दक्षिण एशिया के उस आईने की तरह हैं जिसमें कट्टरता, असहिष्णुता और सत्ता के संरक्षण में पनपती हिंसा साफ दिखाई देती है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन, जमीन हड़पना, झूठे मुकदमे और अब खुलेआम हत्या। यह सब उस देश में हो रहा है जो खुद को इस्लामी गणराज्य कहता है और बराबरी का दावा करता है। सवाल यह है कि क्या वहां हिंदू की जान की कोई कीमत है?

बांग्लादेश की कहानी भी अब अलग नहीं रही। कभी जिसे धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण बताया जाता था, वही देश आज अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। एक के बाद एक हत्याएं, महिलाओं के साथ बर्बरता और प्रशासन की कमजोर प्रतिक्रिया यह बताती है कि समस्या केवल अपराधियों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी है।

सबसे चिंताजनक पहलू अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी है। मानवाधिकार की दुहाई देने वाले वैश्विक मंच, शक्तिशाली देश और संस्थाएं इन घटनाओं पर या तो औपचारिक बयान देकर चुप हो जाते हैं या पूरी तरह नजरें फेर लेते हैं। यह चुप्पी बहुत कुछ कहती है। यह दशार्ती है कि मानवाधिकार अब नैतिक मूल्य नहीं बल्कि सुविधा के अनुसार इस्तेमाल होने वाला हथियार बन चुके हैं। जहां आर्थिक हित, सामरिक समीकरण या राजनीतिक लाभ आड़े आते हैं, वहां इंसानी जान की कीमत शून्य हो जाती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह चुप्पी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को और दुस्साहसी बनाती है। जब उन्हें पता होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस दबाव नहीं बनेगा, तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार एक नियमित प्रक्रिया बन जाती है। वहीं भारत के लिए यह मुद्दा केवल भावनात्मक या धार्मिक नहीं है बल्कि रणनीतिक भी है। सीमापार अस्थिरता, कट्टरता और अल्पसंख्यकों का दमन क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है।

भारत को इस विषय पर स्पष्ट, कठोर और निरंतर रुख अपनाना होगा। केवल बयान देना पर्याप्त नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को बार बार उठाना होगा, तथ्यों के साथ और दबाव के साथ। कूटनीति में शिष्टता जरूरी है लेकिन अन्याय के सामने नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। भारत को यह भी साफ कहना होगा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी देश का आंतरिक मामला नहीं बल्कि सभ्य समाज की कसौटी है।

शक्ति, रणनीति और शहादत का संगम है भारतीय सेना

देश की आजादी के बाद भारतीय सेना पांच बड़े युद्ध लड़ चुकी है, जिनमें चार पाकिस्तान के खिलाफ और एक चीन के साथ लड़ा था। देश की आजादी के बाद 1947-48 में हुए भारत-पाक युद्ध को 'कश्मीर युद्ध' नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद कश्मीर का भारत में विलय हुआ था।

प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हम 78वां सेना दिवस मना रहे हैं। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थलसेना के अदम्य साहस, जांबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और उसकी शहादत को याद करता है। इस विशेष अवसर पर जवानों के दस्ते और अलग-अलग रेजीमेंट की परेड के अलावा झांकियां भी निकाली जाती हैं और उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी दी जाती है, जिन्होंने

अजीत शर्मा

देश और लोगों की सलामती के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 15 जनवरी को ही यह दिवस मनाए जाने का विशेष कारण यही है कि 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल केएम करियप्पा आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ बने थे। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। जनरल फ्रांसिस बुचर भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ थे।1953 में वे भारतीय सेना से सेवानिवृत हुए और 94 वर्ष की आयु में 1993 में उनका निधन हुआ। केएम करियप्पा दूसरे ऐसे सेना अधिकारी थे,

जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी।

भारतीय थल सेना का गठन ईस्ट इंडिया कम्पनी की सैन्य टुकड़ी के रूप में कोलकाता में 1776 में हुआ था, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना बनी और देश की आजादी के बाद इसे 'भारतीय थल सेना' नाम दिया गया। भारतीय सेना की 53 छावनियां और 9 आर्मी बेस हैं और चीन तथा अमेरिका के साथ भारतीय सेना दुनिया की तीन सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल है। हमारी सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ी योगदानकताओं में से एक है। यह दुनिया की कुछेक ऐसी सेनाओं में से एक है, जिसने कभी भी अपनी ओर से युद्ध की शुरूआत नहीं की। भारतीय सेना के ध्वज का बैकग्राउंड लाल रंग का है, ऊपर बायीं ओर तिरंगा झंडा, दायीं ओर भारत का राष्ट्रीय चिह्न और तलवार हैं। सेना दिवस के अवसर पर सेना प्रमुख को सलामी दी जाती रही है लेकिन 2020 में पहली बार सेना प्रमुख के स्थान पर देश के प्रथम सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत को सलामी दी गई थी।

देश की आजादी के बाद भारतीय सेना पांच बड़े युद्ध लड़ चुकी है, जिनमें चार पाकिस्तान के खिलाफ और एक चीन के साथ लड़ा था। देश की आजादी के बाद 1947-48 में हुए भारत-पाक युद्ध को 'कश्मीर युद्ध' नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। 1962 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा धोखे से थाग-ला-रिज पर भारतीय सेना पर हमला बोल दिया गया था। उस जमाने में भातीय सेना के पास स्वचालित और आधुनिक हथियार नहीं होते थे, इसलिए चीन को रणनीतिक बढ़त मिली थी। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। 13 दिनों तक चले उस युद्ध के बाद ही पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तानी जनरल नियाजी के साथ 90 हजार पाक सैनिकों ने जांबाज भारतीय सेना के समक्ष हथियार डाल दिए थे। मई से जुलाई 1999 तक चले कारगिल युद्ध में तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था।

आज पूरी दुनिया भारतीय सेना का लोहा मानती है। आधुनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय सेना एक विश्वस्तरीय सेना है। सेना दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर चीन द्वारा वर्तमान में लगातार पेश की जा रही चुनौतियों के दौर में भारतीय सेना की निरन्तर बढ़ती ताकत का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। 2025 की 'ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट' के अनुसार भारतीय सेना की गिनती दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेनाओं में की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय थल सेना के जखीरे में कई तरह के आधुनिक हथियार शामिल हैं, जिनमें आधुनिक टैंकों के साथ बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। भारत की थल सेना के पास चार हजार से अधिक टैंक हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के जखीरे में एक लाख से अधिक आर्म्ड व्हीकल भी शामिल हैं। थल सेना के पास 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलिरी, 3300 हल्की आर्टिलिरी भी हैं तथा थल सेना के बेड़े में करीब 1500 रॉकेट आर्टिलरी भी शामिल हैं।

भारतीय सैन्यबल में 14.45 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सेना में 12 लाख से ज्यादा आरक्षित बल तथा बीस लाख अर्धसैनिक बल हैं। भारतीय थलसेना में 4600 से ज्यादा टैंक टी-72, टी-90, अर्जुन एमके-1, अर्जुन एमके-2 इत्यादि टैंक, 5 हजार से ज्यादा तोपें, 290 स्वचालित तोपें, 290 से ज्यादा रॉकेट तोपें तथा 8600 बख्तरबंद वाहन शमिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय थलसेना हर परिस्थिति में चीनी सेना से बेहतर और अनुभवी है, जिसके पास युद्ध का बड़ा अनुभव है, जो कि विश्व में शायद ही किसी अन्य देश के पास हो। भले ही चीन के पास भारत से ज्यादा बड़ी सेना और सैन्य साजो-सामान है लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया में किसी के लिए भी इस तथ्य को नजरअंदाज करना संभव नहीं हो सकता कि भारत की सेना को अब धरती पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है और सेना के विभिन्न अंगों के पास ऐसे-ऐसे खतरनाक हथियार हैं, जो चीनी सेना के पास भी नहीं हैं। धरती पर लड़ी जाने वाली लड़ाईयों के लिए भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में होती है और कहा जाता है कि अगर किसी सेना में अंग्रेज अधिकारी, अमेरिकी हथियार और भारतीय सैनिक हों तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना असंभव होगा। जापान के एक आकलन के मुताबिक भारतीय थलसेना चीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिन्द महासागर के मध्य में होने के कारण भारत की रणनीतिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है और दक्षिण एशिया में अब भारत का काफी प्रभाव है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट सीएनएन की एक रिपोर्ट में भी दावा किया जा चुका है कि भारत की ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है और युद्ध की स्थिति में भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। बोस्टन में हार्वर्ड केनेडी स्कूल के बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स तथा वाशिंगटन के एक अमेरिकी सुरक्षा केन्द्र के अध्ययन में कहा जा चुका है कि भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है और चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं फटकती।

पढ़ने की लौ एवं किताबों से नाता अटूट है

53 वें भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी 2026 तक नौ दिनों के किताबों के जमावडे ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि किताबों से नाता कभी नहीं टूट पायेगा। इस मेले में 35 से अधिक देशों के एक हजार से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। यह भव्य विश्व पुस्तक मेला केवल पुस्तकों की खरीद-फरोख्त का आयोजन नहीं है, बल्कि यह उस जीवंत पुस्तक-संस्कृति का उत्सव है, जिसे अनेक लोग डिजिटल युग में कमजोर मानने लगे थे।

एक-एक किलोमीटर लंबी कतारें, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की उत्सुक भागीदारी और पुस्तकों के प्रति बढ़ता आकर्षण इस धारणा को स्वस्थ करता है कि पुस्तकें जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी। इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमों पर अपार पाठ्य सामग्री एवं साहित्य उपलब्ध होने के बावजूद पुस्तक मेलों

सचिन तोमर

में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? छपी हुई पुस्तकें एवं शब्द केवल ज्ञान, जिज्ञासा और मनोरंजन की विशाल दुनिया के दरवाजे नहीं खोलते, वे हमें गंध, स्पर्श, संवेदना, सोच, अनुभूति की प्रेरक, अनुकरणीय एवं रोमांचक दुनिया में भी ले जाते हैं। इस वर्ष के पुस्तक मेले के दृश्य पुस्तक-संस्कृति के प्रति नई आशा, नया विश्वास और नया उत्साह पैदा करते हैं। यह मेला स्पष्ट संकेत देता है कि पढ़ने की प्रवृत्ति केवल जीवित ही नहीं है, बल्कि नए पंखों के साथ उड़ान भर रही है। पुस्तक मेला वस्तुतः एक विश्व उत्सव है-ऐसा उत्सव जो ज्ञान, विचार, कल्पना और संवाद को एक साझा मंच देता है। दुनिया भर में पुस्तकों के दायरे को पहचानने, उन्हें प्रोत्साहित करने और संस्कृतियों को जोड़ने के लिए यह आयोजन अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत कड़ी तथा पीढ़ियों और सभ्यताओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यही कारण है कि यूनेस्को हर वर्ष पुस्तक उद्योग के तीन प्रमुख क्षेत्रों-प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और पुस्तकालयों के अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है, ताकि पुस्तक-संस्कृति की प्रेरणा पूरे वर्ष बनी रहे।

यह पहल इस बात का प्रमाण है कि पुस्तकें केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक संवाद और मानवीय एकता का भी आधार हैं। किताबें अपने सभी रूपों में-मुद्रित, ई-बुक, ऑडियो हमें सीखने, सोचने और स्वयं को सशक्त बनाने का अवसर देती हैं। वे हमारा मनोरंजन करती हैं, हमें

दुनिया को समझने में मदद करती हैं और दूसरों की दुनिया में झांकने का अवसर देती हैं। इस साल का मेला 'भारतीय सैन्य इतिहासः वीरता और ज्ञान/75' थीम पर आधारित है, जो भारत की रक्षा बलों के महत्वपूर्ण पलों, योगदानों और कहानियों पर ध्यान केंद्रित करता है। 'थीम मंडप 2026' दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है। यह मंडप भारत की सैन्य विरासत के 75 वर्षों की ऐतिहासिक और निर्णायक यात्रा को दिखा रहा है, जिसकी जड़ें शौर्य, प्रज्ञा और नैतिक मूल्यों में निहित हैं. इसमें कथाओं, दृश्यात्मक प्रस्तुतियों और संवाद के माध्यम से 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर 2025 तक भारत की सैन्य यात्रा को रेखांकित करता है।

दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में एक प्रतीकात्मक उत्सव बन चुका है। इस मेले में विश्वप्रसिद्ध लेखकों का आगमन होता है, साहित्यिक संवाद, विमर्श और चचाएं होती हैं। विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स जैसे विश्व साहित्य के स्तंभों से लेकर भारतीय भाषाओं के महान साहित्यकारों तक की रचनाएं यहाँ पाठकों को एक साथ उपलब्ध होती हैं। यह मेला भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच देता है और साथ ही विश्व साहित्य को भारतीय पाठकों से जोड़ता है।

पुस्तकों को 'ज्ञान का बाग' कहा गया है। जो व्यक्ति पुस्तकों से सच्ची दोस्ती कर लेता है, उसे जीवन भर ज्ञान का संबल मिलता है। कठिन समय में पुस्तकें मित्र की तरह साथ देती हैं, मार्गदर्शन करती हैं और समाधान की दिशा दिखाती हैं। पुस्तक का महत्व सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक है। किसी भी युग में, किसी भी तकनीकी आंधी में उसका महत्व कम नहीं हो सकता। इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अनेक क्रांतियां आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन पुस्तक-संस्कृति अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता बनाए रखेगी। कारण स्पष्ट है-पुस्तकें केवल सूचना नहीं देतीं, वे चिंतन, मनन और विवेक का विकास करती हैं। तकनीक ने ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति अवश्य की है, लेकिन यह हर समय संभव नहीं कि किताबों के स्थान पर केवल स्क्रीन से पढ़ा जाए। पुस्तक का स्पर्श, उसकी सुगंध, पन्नों को पलटने का अनुभव और पढ़ते हुए होने वाला एकांत संवाद-ये सभी तत्व पुस्तक को विशिष्ट बनाते हैं। पुस्तकें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, सोचने-समझने का दायरा बढ़ाती हैं और व्यक्ति को आत्मअनुशासन सिखाती हैं। पुस्तकें जाग्रत देवता के समान हैं। उनका अध्ययन, मनन और चिंतन तत्काल लाभ देता है। महात्मा गांधी के जीवन पर गीता, टॉल्स्टॉय और थोरो के विचारों का गहरा प्रभाव था। इसी तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैचारिक निर्माण और वैश्विक छवि के निर्माण में पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे स्वयं एक सजग पाठक रहे हैं और पुस्तक-संस्कृति को जीवंत करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

पीएम मोदी ने 'मन की बात' जैसे अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ने, लिखने और विचार करने की संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाया है। उनका संदेश 'बुकें दे, बुके नहीं' केवल एक प्रतीकात्मक नारा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दृष्टि है-जहाँ उपहार में फूलों के गुलदस्ते की बजाय ज्ञान का उपहार देने की प्रेरणा दी गई है। वे मानते हैं कि सत्साहित्य की शक्ति तोप, टैंक और परमाणु अस्त्रों से भी अधिक है, क्योंकि हथियार ध्वंस करते हैं, जबकि साहित्य मानव-मूल्यों में आस्था पैदा करता है और स्थायी परिवर्तन लाता है। सत्साहित्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है-ऐसा परिवर्तन जो सत्ता और कानून से किए गए परिवर्तनों से कहीं अधिक टिकाऊ होता है। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी भारत के परिवर्तन में पुस्तक-संस्कृति और सत्साहित्य की निर्णायक भूमिका को स्वीकारते हैं। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, स्थानीय साहित्य का सम्मान और पठन-संस्कृति को प्रोत्साहन देने की दिशा में ठोस पहलें देखने को मिलती हैं।

पुस्तकें चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम साधन हैं। उत्तम विचारों से युक्त पुस्तकों के प्रचार-प्रसार से युवाओं को नई दिशा दी जा सकती है। देश की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जा सकता है और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। पुस्तकें प्रेरणा का भंडार हैं, उन्हें पढ़कर व्यक्ति के भीतर कुछ महान करने की आकांक्षा जागती है। वे कल्पवृक्ष भी हैं और कामधेनु भी, क्योंकि उनकी छाया में मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानता है। आज का इंसान घर बदलता है, पहनावा बदलता है, रिश्ते और मित्र बदलता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है क्योंकि उसने पुस्तकरूपी कल्पवृक्ष की छाया छोड़ दी है। पुस्तकें व्यक्ति को बदलने का मार्ग दिखाती हैं-सोच, व्यवहार और दृष्टि को सकारात्मक दिशा देती हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं बदलता, वह अपनी मंजिल नहीं पा सकता। आत्मानुशासन, आत्मचिंतन और आत्मविकास-ये सभी पुस्तक-संस्कृति की देन हैं।

इंटरनेट और ई-पुस्तकों की बढ़ती पहुँच के बावजूद छपी हुई किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है। वे आज भी प्रासंगिक हैं और रहेंगी। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन-'साहित्य वह जादू की छड़ी है, जो पशुओं में, ईंट-पत्थरों में और पेड़-पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है', आज भी उतना ही सार्थक है। निश्चित ही, विश्व पुस्तक मेला की प्रेरणा भारतीय जन-चेतना को झकझोर रही है और उन्हें नए भारत-सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित कर रही है। साररूप में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला पुस्तक-संस्कृति और पढ़ने की प्रवृत्ति को नए पंख देने वाला एक अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक आयोजन है। इसका उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकें ज्ञान का वाहक हैं जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं, सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोती हैं और समाज को दिशा देती हैं। यह मेला केवल पुस्तकों का नहीं, विचारों का, संस्कारों का और भविष्य का मेला है-जहाँ शब्द समाज का निर्माण करते हैं और पन्ने इतिहास की दिशा तय करते हैं।

मिलेनियल युवाओं पर भाजपा का फोकस

भाजपा में युवा नेताओं की फौज

भाजपा ने युवाओं की आकांक्षा और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को बनाना शुरू किया है। तभी उसने अपने सभी 16 हजार मंडल अध्यक्ष 45 साल से कम उम्र के बनाए हैं। कह सकते हैं कि 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस रूपांतरण को सहज तरीक से क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व पूरा करना है।

ललित कुमार

भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चयनित किया गया तो कई प्रकार से इसकी व्याख्या हुई। उनको एक ऐसे दल का नेतृत्व मिला है, जिसकी सरकार देश में है और देश के ज्यादातर राज्यों में भी है। नितिन नबीन को 14 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी मिली है। देश के सभी जिलों में पार्टी का अपना कार्यालय है, जहां से जमीनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका आधार पूरे देश में फैल गया है। परंतु यह सारी उपलब्धियां भाजपा ने धैर्य के साथ और अपने महान नेताओं के परिश्रम से प्राप्त की है। नितिन नबीन को उन महान नेताओं की उपलब्धियों को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि उसका विस्तार भी करना है। इसलिए नितिन नबीन को जो मिला है, व्यापकता की दृष्टि से उसका

आकलन करते हुए इस बात का भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि इसकी निरंतरता कायम रखने के लिए कितना परिश्रम करना होगा और उसके रास्ते में क्या चुनौतियां आएंगी।

भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनौतियों को ध्यान में रख कर ही नितिन नबीन जैसे युवा, मेहनती और जमीनी राजनीति की गंभीरता व जटिलता को समझने वाले नेता को अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने पद संभालते है इसका परिचय भी दिया। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में सभी पदाधिकारियों के साथ लगातार नौ घंटे की मैराथन बैठक की, जिसमें एक समय जेपी नड्डा भी शामिल हुए और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी उपस्थित रहे।

वास्तविकता यह है कि नितिन नबीन के सामने संगठन के विस्तार की निरंतरता कायम रखने की चुनौती है तो साथ ही जितने प्रदेशों में भाजपा और एनडीए की सरकार है उन प्रदेशों की सरकारों की पुनर्वापसी सुनिश्चित करते हुए नए प्रदेशों में सत्ता प्राप्त करने की चुनौती भी है। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप भाजपा को तैयार करने की भी एक बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से उनको भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं और संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ का सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा। आखिर वे भी स्वंयसेवक रहे हैं और संघ के आदर्शों के अनुरूप राजनीति की है। तभी उनके निर्विरोध चयन में संघ की सहमति भी सम्मिलित है।

पहले बदलती परिस्थितियों की ही बात करें तो स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को जेन जी और मिलेनियल युवाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के चयन की घोषणा के लिए आयोजित संगठन पर्व में कहा कि नितिन नबीन एक तरह से मिलेनियल युवा हैं। ध्यान रहे भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसलिए भाजपा ने युवाओं की आकांक्षा और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को बनाना शुरू किया है। तभी उसने अपने सभी 16 हजार मंडल अध्यक्ष 45 साल से कम उम्र के बनाए हैं। कह सकते हैं कि 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस रूपांतरण को सहज तरीक से क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व पूरा करना है। मंडल से लेकर प्रदेश और केंद्र तक साथ ही स्थानीय निकायों से लेकर राज्य तक में युवाओं का नेतृत्व स्थापित हो और पार्टी के पुराने नेताओं के साथ समन्वय बना कर काम किया जाए, यह सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होगी।

बहुत जल्दी देश में जनगणना का कार्य शुरू होने वाला है। पहले आवासों की गणना होगी और अगले साल जाति के साथ व्यक्तियों की गिनती होगी। 1931 के बाद पहली बार जातीय गणना होने वाली है।

देश के सैकड़ों जातियों की जनसंख्या के आंकड़े सामने आएंगे। उसका गुणात्मक प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बदलाव के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए तैयार करने का काम नए नेतृत्व को करना है। ध्यान रहे भाजपा को लेकर एक समय यह धारणा रही थी कि वह ब्राह्मणों और वैश्यों की पार्टी है।

परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वह धारणा बदली है। भाजपा पूरे देश में व्यापक हिंदुत्व की धारणा स्थापित करने में कामयाब रही है और हिंदुत्व के साथ जातियों का बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया है। मंडल और कमंडल की राजनीति का जो विभाजन नब्बे के दशक से चला आ रहा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया है। अब मंडल और कमंडल दोनों एक हैं और यही कारण है कि कांग्रेस व समस्त प्रादेशिक पार्टियों को भाजपा के हाथों इतनी करारी हार झेलनी पड़ रही है। इस जुड़ाव को और मजबूत करने की

जिम्मेदारी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के ऊपर है। जनगणना के बाद तीन बड़ी परिघटना होने वाली है। पहली तो 'एक देश, एक चुनाव' की तैयारी है। दूसरी महिला आरक्षण लागू होना है और तीसरी परिसीमन किया जाना है। 'एक देश, एक चुनाव' के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक पेश किया जा चुका है, जिस पर संयुक्त संसदीय समिति विचार कर रही है। संसद से कानून पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। उसके लिए भाजपा संगठन को और शक्तिशाली करने की आवश्यकता होगी। उसके साथ ही संभव है कि नारी शक्ति वंदन कानून को भी लागू किया जाए, जिसके तहत महिलाओं के लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी।

परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों चुनौतीपूर्ण कार्य है। दक्षिण भारत में परिसीमन का विरोध हो रहा है और इसे उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से रोकने का काम भाजपा को करना है। भाजपा संगठन की यह जिम्मेदारी होगी वह उत्तर से दक्षिण तक आम लोगों को भरोसा दिलाए कि परिसीमन से किसी के अधिकार में कटौती नहीं हो रही है और न किसी प्रदेश की राजनीतिक हैसियत घटाई जा रही है। सभी राज्यों का पहले की तरह सम्मान और महत्व बना रहेगा। इसी तरह महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग की महिलाओं को मिलेगा, इस पुरानी धारणा के जवाब में भी भाजपा को देश भर में जागरुकता अभियान चलाना होगा और सभी जातीय समूहों को भरोसा दिलाना होगा।

इसके बाद नए भाजपा अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक है। इस समय 14 राज्यों में भाजपा की सरकार है यानी भाजपा का अपना मुख्यमंत्री है और छह अन्य राज्यों में सहयोगी पार्टी की सरकार है। यानी 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 16 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से नौ राज्यों में भाजपा की सरकार है। इसके बाद लोकसभा के साथ तीन राज्यों के चुनाव होंगे और लोकसभा के तुरंत बाद तीन और राज्यों के चुनाव होंगे। उन छह राज्यों से चार में भाजपा की सरकार है और एक राज्य में सहयोगी पार्टी की सरकार है। उसके अगले साल यानी 2030 में दिल्ली और बिहार के चुनाव होंगे, दोनों जगह एनडीए की सरकार है। उस समय तक नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने में कोई संदेह नहीं दिख रहा है।

ध्यान रहे उनका कार्यकाल जनवरी 2029 में पूरा हो रहा है लेकिन उस समय तक लोकसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी रहेगी इसलिए बदलाव नहीं होगा, बल्कि उनको विस्तार दिया जाएगा, जो 2030 के अंत में होने वाले उनके गृह प्रदेश बिहार के चुनाव तक जारी रह सकता है।

इसका अर्थ है कि 2030 के अंत तक लोकसभा और 24 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। केंद्र में भाजपा अपना प्रदर्शन बेहतर करे और 2014 व 2019 की तरह पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उन राज्यों में जहां भाजपा या उसकी सहयोगी पार्टी की सरकार है वहां उस सरकार की पुनर्वापसी हो और जिन

नए भाजपा अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक है। इस समय 14 राज्यों में भाजपा की सरकार है यानी भाजपा का अपना मुख्यमंत्री है और छह अन्य राज्यों में सहयोगी पार्टी की सरकार है। यानी 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 16 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से नौ राज्यों में भाजपा की सरकार है।

राज्यों में अभी तक भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई है वहां भाजपा की सरकार बने यह भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने एक चुनौती है। उनके गृह प्रदेश बिहार में आज तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। क्या उनके कार्यकाल में ऐसा हो पाएगा यह भी देखने की बात होगी। उनके सामने तात्कालिक चुनौतियों में पांच राज्यों का चुनाव है, जिसमें सबसे भीषण लड़ाई पश्चिम बंगाल की है।

पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का एक सांस्कृतिक जुड़ाव है। बिहार 1911 तक बंगाल का ही हिस्सा था। आज भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग बंगाल के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन नबीन स्वंय जिस जाति से आते हैं वह पश्चिम बंगाल में बेहद प्रभावशाली है। बांग्ला भद्रलोक में कायस्थ बड़ा अहम स्थान रखते हैं। वे सिर्फ धारणा नहीं बनवाते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। अगर नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पश्चिम बंगाल के चुनाव में सक्रिय होते हैं और बांग्ला भद्रलोक के साथ साथ बिहार के मतदाताओं को व्यापक रूप से भाजपा के साथ जोड़ कर भाजपा की जीत सुनिश्चित करते हैं तो उनका राजनीतिक व्यक्तित्व और विशाल बनेगा।

पांच राज्यों का चुनाव भाजपा को व्यापक रूप से पैन इंडिया पार्टी के रूप में स्थापित करने वाला चुनाव है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन चुनावों में इतनी ताकत झोंकी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और अमित शाह की रणनीति दोनों का अधिकतम लाभ भाजपा को मिले यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नितिन नबीन के ऊपर है। उनको अपने राजनीतिक अनुभव, संगठन की शक्ति और अपने परिश्रम से इन राज्यों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी है।

ईरान सुलग रहा है, सत्ता कांप रही है, जनता का डर खत्म हो रहा है

ईरान इस समय उबाल पर है। जो विरोध महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ था वह अब सीधे इस्लामी सत्ता व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की चुनौती बन चुका है। लगातार बारह दिनों से सड़कों पर उतर रही जनता अब केवल नारे नहीं लगा रही बल्कि सत्ता के प्रतीकों को जलाकर यह साफ संदेश दे रही है कि डर की दीवार टूट चुकी है। सरकारी इमारतें, पुलिस चौकियां और प्रशासनिक वाहन जनता के गुस्से का निशाना बन रहे हैं। यह केवल प्रदर्शन नहीं है, यह व्यवस्था के खिलाफ खुला विद्रोह है।

तेहरान से लेकर मशहद, इस्फहान और दर्जनों छोटे शहरों तक हालात एक जैसे हैं। सड़कों पर युवा हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं और अब मध्यम वर्ग भी खुलकर सामने आ चुका है। नारे अब रोटी कपड़ा और नौकरी तक सीमित नहीं रहे। सीधे सर्वोच्च नेता और पूरी इस्लामी व्यवस्था को ललकारा जा रहा

अनिल वशिष्ठ

है। सत्ता के खिलाफ इस तरह की खुली बगावत ईरान के इतिहास में बहुत कम देखी गई है।

हालांकि ईरान सरकार का जवाब भी उतना ही सख्त और बेरहम है। इंटरनेट बंद, मोबाइल सेवाएं ठप, सुरक्षा बलों को खुली छूट और गिरफ्तारियों का अंधाधुंध दौर चल रहा है। दर्जनों मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग जेलों में ठूंस दिए गए हैं। सत्ता यह दिखाना चाहती है कि वह अब भी मजबूत है, लेकिन हकीकत यह है कि डर के बल पर चलने वाली किसी भी व्यवस्था का अंत हमेशा हिंसक होता है। हम आपको यह भी बता दें कि इन हालात के बीच रेजा पहलवी का नाम फिर से उभर रहा है। वह ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं और खुद को देश का वैध क्राउन प्रिंस मानते हैं। हम आपको याद दिला दें कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उनका परिवार देश छोड़ने पर मजबूर हुआ था। तब से वह निर्वासन में हैं और खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष ईरान का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। रेजा पहलवी खुले तौर पर मौजूदा सत्ता को अवैध बताते हैं और सेना तथा जनता से अपील कर रहे हैं कि वह इस्लामी नेतृत्व का साथ छोड़ दें। उनके समर्थक उन्हें ईरान के लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भावनात्मक अपील है या वाकई सत्ता परिवर्तन का कोई ठोस खाका है। सवाल यह भी है कि क्या ईरान में तख्तापलट होने वाला है ?

देखा जाये तो यह सवाल इस समय हर विश्लेषण का केंद्र बना हुआ है। मगर सच्चाई यह है कि ईरान में हालात गंभीर जरूर हैं लेकिन तख्तापलट के लिए संगठित नेतृत्व, सेना का समर्थन और सत्ता संरचना

के भीतर दरार जरूरी होती है। फिलहाल जो दिख रहा है वह जनता का गुस्सा है, लेकिन वह गुस्सा बिखरा हुआ है। कोई एक केंद्रीकृत नेतृत्व नहीं है जो सत्ता संभालने की स्थिति में हो। रेजा पहलवी की लोकप्रियता सोशल मीडिया और प्रवासी ईरानियों में जरूर है, लेकिन देश के भीतर उनके पास न तो संगठन है और न ही जमीन पर नियंत्रण। ईरान की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत और वैचारिक रूप से कट्टर है। रिवोल्यूशनरी गार्ड केवल सेना नहीं बल्कि सत्ता की भी रीढ़ हैं। जब तक इस ढांचे में टूट नहीं होती तब तक तख्तापलट की बात करना जल्दबाजी होगी।

जहां तक यह सवाल है कि क्या राजशाही की वापसी संभव है तो आपको बता दें कि राजशाही की वापसी एक और भावनात्मक कल्पना है। आज का ईरान 1979 वाला ईरान नहीं है। चार दशक की इस्लामी सत्ता ने समाज की संरचना बदल दी है। नई पीढ़ी स्वतंत्रता चाहती है लेकिन जरूरी नहीं कि वह किसी शाह को फिर से गद्दी पर बैठाना चाहती हो। रेजा पहलवी खुद भी खुलकर यह नहीं कहते कि वे राजा बनेंगे। वह सत्ता को जनता के हवाले करने और जनमत संग्रह की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कि राजशाही की वापसी फिलहाल एक नारा भर है, हकीकत नहीं।

ईरान संकट का सामरिक प्रभाव देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान पूरे पश्चिम एशिया की धुरी है। यहां अस्थिरता का मतलब है तेल बाजार में उथल पुथल, खाड़ी क्षेत्र में तनाव और कई देशों में प्रॉक्सी संघर्ष का तेज होना। ईरान के कमजोर होने से उसके समर्थित गुटों की स्थिति भी बदलेगी। इससे इजराइल और अरब देशों के बीच संतुलन बदल सकता है। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां इस मौके को अपने हित में भुनाने की कोशिश करेंगी। दूसरी ओर रूस और चीन भी ईरान को हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका असर केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे क्षेत्र को हिला देगा और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को भी झटका देगा।

देखा जाये तो ईरान में जो हो रहा है वह केवल सत्ता के खिलाफ गुस्सा नहीं बल्कि दशकों की घुटन का विस्फोट है। जनता अब सुधार नहीं बल्कि बदलाव चाहती है। लेकिन बदलाव अपने आप नहीं आता, उसे दिशा देनी पड़ती है। रेजा पहलवी इस विद्रोह का चेहरा बन सकते हैं, लेकिन वह मसले का समाधान नहीं हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए केवल नाम नहीं बल्कि जमीन पर ताकत चाहिए।

अगर यह विद्रोह संगठित नहीं हुआ तो सत्ता इसे बेरहमी से कुचल देगी।

बहरहाल, ईरान आज चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता दमन का है, दूसरा बदलाव का। तख्तापलट होगा या नहीं यह आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि ईरान अब पहले जैसा नहीं रहेगा। डर टूट चुका है और यही किसी भी सत्ता के पतन की पहली सीढ़ी होती है।

भारतीय समाज में बालिकाओं को लेकर ऐतिहासिक रूप से दोहरी मानसिकता रही है। एक ओर देवी स्वरूप में पूजन तो दूसरी ओर जन्म से ही भेदभाव। बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और शिक्षा से वंचित रखना जैसी कुप्रथाएं लंबे समय तक बालिकाओं के भविष्य पर भारी पड़ीं।

अरुण शर्मा

सम्मान, सुरक्षा और समानता का सवाल

भारत में विकास और समानता की चर्चा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसमें बालिकाओं की स्थिति का ईमानदार मूल्यांकन न हो। 23 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस इसी मूल्यांकन और आत्ममंथन का अवसर प्रदान करता है। यह दिन केवल औपचारिक आयोजन या शुभकामनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, सरकार और परिवार–तीनों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसकी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और अवसरों से आंकी जाती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरूआत वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जन-

जागरूकता बढ़ाना और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक समस्याओं पर गंभीर संवाद स्थापित करना रहा है। आजादी के सात दशक बाद भी देश के कई हिस्सों में बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और निर्णय लेने के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि योजनाओं और नीतियों के बावजूद सामाजिक सोच में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं आ पाया।

भारतीय समाज में बालिकाओं को लेकर ऐतिहासिक रूप से दोहरी मानसिकता रही है। एक ओर देवी स्वरूप में पूजन तो दूसरी ओर जन्म से ही भेदभाव। बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और शिक्षा से वंचित रखना जैसी कुप्रथाएं लंबे समय तक बालिकाओं के भविष्य पर भारी पड़ीं। हालांकि समय के साथ कानून बने, जागरूकता बढ़ी और कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले, लेकिन ग्रामीण और वंचित तबकों में आज भी यह समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी हैं।

शिक्षा को बालिका सशक्तिकरण की सबसे मजबूत आधारशिला माना जाता है। शिक्षित बालिका न केवल आत्मनिर्भर बनती है, बल्कि परिवार और समाज को भी आगे ले जाती है। इसी सोच के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं से नामांकन दर में सुधार तो हुआ है, लेकिन स्कूल छोड़ने की समस्या, डिजिटल संसाधनों की कमी और सुरक्षित वातावरण का अभाव आज भी चिंता का विषय बना हुआ है।

स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में भी बालिकाओं की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। कुपोषण, एनीमिया और किशोरावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आज भी बड़ी चुनौती हैं। पर्याप्त पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना सशक्तिकरण की कल्पना अधूरी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें यह याद दिलाता है कि योजनाओं की सफलता तभी मानी जाएगी जब उनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़ी बालिका तक पहुंचे।

बालिकाओं की सुरक्षा आज के समय का सबसे संवेदनशील विषय बन चुका है। घरेलू हिंसा, यौन शोषण, साइबर अपराध और सार्वजनिक स्थलों पर असुरक्षा जैसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चेतावनी हैं। कानूनों के साथ-साथ सामाजिक सोच में बदलाव और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। सुरक्षित वातावरण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

इसके बावजूद, यह भी सच है कि आज की बालिकाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। विज्ञान, खेल, कला, प्रशासन और उद्यमिता में उनकी बढ़ती भागीदारी यह साबित करती है कि अवसर मिलने पर वे किसी से पीछे नहीं हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर खेल मैदान तक, बालिकाएं देश का नाम रोशन कर रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

बालिकाओं के हित में बनाए गए कानून और नीतियां तभी प्रभावी हो सकती हैं, जब समाज उनका ईमानदारी से पालन करे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून मजबूत आधार प्रदान करते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन और सामाजिक स्वीकार्यता समान रूप से जरूरी है। मीडिया की भूमिका भी यहां महत्वपूर्ण हो जाती है, जो सकारात्मक उदाहरणों को सामने लाकर सामाजिक सोच को दिशा दे सकता है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस का असली उद्देश्य केवल एक दिन मनाना नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। यह दिन हमें यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हर बालिका को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक भविष्य मिले। जब एक बालिका सशक्त होती है, तो पूरा समाज मजबूत होता है।

23 जनवरी पर यही संदेश उभरकर सामने आता है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आवश्यकता है उन्हें बराबरी का अवसर देने की, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ कह सकें—मैं सुरक्षित हूं, शिक्षित हूं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हूं।

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका कल्पना नहीं हकीकत है

समुद्र और जमीन की गहराइयों में उतर कर सबूत सामने लायेगी ASI

भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में द्वारका का नाम केवल एक नगर भर नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और सभ्यता की निरंतरता का जीवंत प्रतीक है। अब वही द्वारका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हम आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन द्वारका की खोज को नए सिरे से, अधिक गहराई और गंभीरता के साथ आगे बढाने का निर्णय लिया है। इस बार यह अभियान केवल सतही अध्ययन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन और समुद्र दोनों में गहन खुदाई के जरिये इतिहास

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

की दबी हुई परतों को उजागर करने का प्रयास होगा।

हम आपको बता दें कि अब तक हुए सीमित अध्ययनों में समुद्र के भीतर पत्थर की संरचनाएं, दीवारनुमा अवशेष और मानव बसावट के संकेत मिल चुके हैं। लेकिन इन संकेतों को निर्णायक प्रमाण में बदलने के लिए अरक अब आधुनिक तकनीक, उन्नत उपकरण और विशेषज्ञों की बहुविषयक टीम के साथ आगे बढ़ रहा है। इस नए अभियान का केंद्र गोमती नदी का मुहाना, समुद्री किनारे के वे हिस्से जहां अब तक खुदाई नहीं हुई, और बेट द्वारका जैसे क्षेत्र होंगे।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अरक के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह खुदाई केवल धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह समझना है कि प्राचीन

द्वारका में जीवन कैसा था, वहां का शहरी ढांचा कैसा रहा होगा, व्यापार और संस्कृति किस स्तर पर थी और किस ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत यह नगर समुद्र में विलीन हुआ। यह अभियान भारत के समुद्री इतिहास, तटीय सभ्यता और प्राचीन नगर नियोजन की समझ को भी नया आयाम देगा।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका की समुद्री विरासत पर पहले ही सार्वजनिक रूप से ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। हम आपको याद दिला दें कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अरब सागर की उथली लहरों के भीतर गहराई तक उतरकर प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेषों के पास हाथ जोड़े थे तब पूरा भारत मंत्रमुग्ध हो उठा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र के भीतर स्थित उस स्थल पर स्कूबा डाइविंग करते हुए भगवान श्रीकृष्ण की नगरी को अपनी आंखों से देखा था, उसे प्रणाम किया था और इसे 'दिव्य अनुभव' बताया था। उस दृश्य ने हजारों वर्षों से मौन इतिहास को एक जीवंत रूप में सामने ला दिया था। अब अरककी यह नई पहल इस विषय को ठोस ऐतिहासिक विमर्श में बदलने जा रही है।

देखा जाये तो सदियों तक द्वारका को मिथक कहकर खारिज किया गया, उसे आस्था का विषय कहकर इतिहास की किताबों से बाहर रखा गया। लेकिन अब वैज्ञानिक साक्ष्य सामने आने लगे हैं। साथ ही धार्मिक दृष्टि से द्वारका का महत्व असाधारण है। यह वह भूमि है जिसे भगवान श्रीकृष्ण की कर्मभूमि माना जाता है। पुराणों और महाभारत में वर्णित द्वारका कोई साधारण नगर नहीं थी, बल्कि एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और शक्तिशाली नगरी थी। कहा जाता है कि श्रीकृष्ण ने मथुरा त्याग कर समुद्र तट पर इस नगर की स्थापना की थी ताकि अपने लोगों को निरंतर आक्रमणों से बचा सकें। यह निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी क्रांतिकारी था।

द्वारका सप्तपुरी में गिनी जाती है और चारधाम परंपरा में इसका स्थान सर्वोच्च है। यहां स्थित द्वारकाधीश मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन परंपरा की जीवंतता का अनुपम उदाहरण है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस इतिहास से जुडने के लिए जो पीढ़ियों से उनकी चेतना में प्रवाहित होता रहा है।

आज जब अरकसमुद्र की गहराइयों में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो वह केवल पत्थर और दीवारें खोजने नहीं जा रहा। वह उस स्मृति को खोजने जा रहा है जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। यह खोज उन प्रश्नों को चुनौती देती है जो कहते रहे कि भारत का प्राचीन इतिहास कल्पना पर आधारित है। द्वारका की खुदाई यह साबित करने की दिशा में कदम है कि हमारी परंपराएं, हमारे ग्रंथ और हमारी आस्थाएं किसी शून्य से नहीं उपजीं, बल्कि ठोस सामाजिक और भौगोलिक यथार्थ पर आधारित थीं।

यहां एक तीखा प्रश्न भी खड़ा होता है। यदि किसी अन्य सभ्यता से जुड़ा नगर समुद्र में डूबा मिलता, तो क्या उसे वैश्विक इतिहास की महान खोज नहीं कहा जाता। फिर द्वारका के साथ संकोच क्यों? क्या इसलिए कि यह भारत की धार्मिक चेतना से जुड़ी है। अरक की यह पहल उस मानसिकता पर भी प्रहार है जो भारतीय इतिहास को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखती रही।

देखा जाये तो धार्मिक महत्व के साथ-साथ द्वारका सांस्कृतिक स्वाभिमान का विषय भी है। यह हमें याद दिलाती है कि भारत केवल आक्रमणों और पराजयों की कहानी नहीं है, बल्कि नगर निर्माण, समुद्री व्यापार और सभ्य जीवन की भी गौरवशाली परंपरा रहा है। द्वारका की खोज उस आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करती है जो हमें अपने अतीत से कटने नहीं देता।

बहरहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि द्वारका की खुदाई केवल अतीत को जानने का प्रयास नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का साहसिक कदम है। यह धर्म और विज्ञान के टकराव की नहीं, बल्कि उनके संवाद की कहानी है। यदि यह खोज अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, तो यह केवल इतिहास की किताबों में एक नया अध्याय नहीं जोड़ेगी, बल्कि भारत की आत्मा को वह सम्मान लौटाएगी जिसकी वह सदियों से प्रतीक्षा कर रही है।

अरावली पर्वतमाला: अवैध खनन रोकने में जनसहभागिता भी जरूरी

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

सर्वोच्च न्यायालय की अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर जो चिंता देखी गई है वह अपने आपमें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अरावली पर्वतमाला को खोखला करने में अवैध खनन गतिविधियों की प्रमुख भूमिका रही है। यही कारण है कि 21 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की बैंच ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और समस्या के मूल कारण अवैध खनन पर रोक पर जोर दिया है। 21 जनवरी के निदेर्शों को स्पष्टता की दृष्टि से दो भागों में समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी में जहां अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी रोक और इसकी कार्ययोजना के निर्देष दिए हैं वहीं अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के मुद्दे का अलग अलग देखने पर जोर दिया है। अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर के आदेष को दिसंबर के केप्ट इन एवियांस के आदेश को यथावत रखा हैं और विशेषज्ञों की कमेटी बनाने के लिए नाम व सुझाव मांगे है। कमोबेस चार सप्ताह में दुबारा सुनवाई तक कार्ययोजना और विशेषज्ञों के नाम और सुझाव का समय दिया गया है। पर अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अधिक गंभीरता जताई है।

अरावली पर्वतमाला को लेकर वैध और अवैध खनन की बहस को अलग रखकर देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि अरावली पर्वतमाला को वैध खनन से अधिक अवैध खनन ने नुकसान पहुंचाया है। यह चिंता केवल पर्यावरणविदों की ही नहीं अपितु समूचे समाज और समूचे देश की इस मायने में है कि अरावली पर्वतमाला एक मोटे अनुमान के अनुसार 2 अरब पुरानी प्रोटेरोजोइक युग में निर्माण हुआ माना जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और गुजरात तक अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान का बड़ा क्षेत्र 20 जिले अरावली पर्वतमाला में आते हैं। अरावली पर्वतमाला की कोख में मेसेनरी स्टोन से लेकर क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के अपार भण्डार है। देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की तुलना में हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में अधिक नुकसान पहुंचाया गया है। खैर आरोप प्रत्यारोप का ना तो यह समय है और ना ही इससे कोई निकष निकलने वाला है। पर एक बात साफ है कि अरावली पर्वतमाला को संरक्षित रखना समय की मांग और भविष्य के लिए आज की आवश्यकता है।

अरावली पर्वतमाला देखा जाए तो थार के मरुस्थल के फैलाव को रोकने की प्राकृतिक

तारबंदी या दीवार माना जा सकता है। एक तरह से मरुस्थलीय विस्तार पर प्राकृतिक अवरोध है। जल और वायु को संरक्षित करता है तो जैव विविधता को संरक्षित करती है। अरावली पर्वतमाला में जैव विविधता के साथ ही वन्यजीव गलियारे विकसित है। दरअसल अरावली पर्वतमाला केवल प्राकृतिक अवस्था नहीं है बल्कि अन्य सब कारकों के साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। अरावली श्रृंखला धूलभरी आंधियों से संरक्षित करती है तो जल संरक्षण और नदियों का स्रोत भी है। वन्य जीवों सहित जैव विविधता को अपनी कोख में संरक्षित किये हुए हैं। अब दोहरा संकट सामने हैं। एक और अरावली के संरक्षण की आवष्यकता है तो दूसरी और बेशकीमती खनिजों का खनन भी समय की मांग है। हांलाकि जैसा नवंबर के आदेश के बाद विशेषज्ञों के विष्लेषण सामने आये हैं वह कहानी कुछ और ही कहता है पर यह विवाद या बहस का विषय हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अवैध खनन एक प्रमुख कारण रहा है। हांलाकि दिसंबर के केप्ट इन एवियांस आदेश के साथ ही राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने प्रदेष में अरावली क्षेत्र के 20 जिलों में 29 दिसंबर, 25 से 15 जनवरी, 2026 तक अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए। अभियान के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1445 प्रकरण दर्ज हुए और संबंधित पुलिस थानों में 320 एफआईआर दर्ज कराई गई। इस दौरान 140 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई। 82898 टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया गया। अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 68 एक्सक्वेटर, जेसीबी सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए और 1223 वाहन जब्त कर संबंधित पुलिस थानों को सुपुर्द किये गये। अभियान के दौरान जुमार्ने के रुप में 9 करोड़ 86 लाख रुपए की वसूली कर राजकोष में जमा किए गए। यह भौतिक उपलब्धि रही है। खैर आंकड़ों को अलग रख भी दिया जाए तो राजस्थान सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ ईमानदार प्रयास किये हैं। केन्द्र सरकार ने भी अरावली संरक्षण को लेकर कार्ययोजना घोषित की है। इस क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध तो है ही।

चिंतनीय और गंभीर सवाल यह उठता है कि नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय के अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के कुछ समय बाद जिस तरह से अरावली संरक्षण के लिए देश व्यापी आवाज उठी और जिस तरह से डीपी लगाने और प्रदर्शन आदि का दौर चला वह दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवंबर के आदेश को केप्ट इन एवियांस करने के साथ ही ना जाने कहां नेपथ्य में चला गया। हांलाकि अरावली पर्वतमाला को लेकर जिस तरह से

आवाज उठाई गई वह जागरुकता की मिसाल मानी जा सकती है। बाद में तो कुछ छुट-पुट आवाज ही सुनाई दी। जबकि मीडिया लगातार अग्रलेखों व अन्य तरह से इस मुद्दे को जीवित रखे रहा। सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम टिप्पणी ने अवैध खनन के प्रति जिस तरह से गंभीरता दिखाई है और रोक लगाने के निर्देश दिए हैं वह समस्या की जड़ तक पहुंचने में सहायक है। जब हम सब मानकर चल रहे हैं और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक तरह से मोहर लगा दी है कि समस्या की जड़ अवैध खनन गतिविधियां है तो फिर आवाज की गूंज अवैध खनन पर रोक की भी तेज होनी चाहिए। अब सवाल यह भी उठता है कि अवैध खनन करने वाले कौन है? अरावली पर्वतमाला को खोखला करने वाले कौन है? कोई आप हम में से आम आदमी तो हो नहीं सकता। निश्चित रुप से प्रभावशाली लोगों का ही यह काम है। मजे की बात यह है कि इस तरह के लोगों में से कुछ तत्व ही आंदोलन के अगुवा बन जाते हैं। फिर धरातलीय बात की जायं तो यह मानना ही पड़ेगा कि स्थानीय लोगों, स्थानीय प्रशासन और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से छुप कर अवैध खनन होता हो तो यह भी गले उतरने वाली बात नहीं हो सकती। ऐसे में भले ही आरोप प्रत्यारोप किसी पर भी लगे, कहने को सरकार और सरकारी मशीनरी को दोषी बताया जाएं पर आमआदमी और गैरसरकारी संस्थाओं, सोशल एक्टिविस्टों की भी समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है। तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि राजस्थान सरकार द्वारा या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा अभियान चलाये जाते हैं या अन्य सामान्य परिस्थितियों में अवैध खनन गतिविधियों की शिकायत भूल भटकी ही प्राप्त होती है। बात कड़बी अवश्य लग सकती है पर यह भी सही है कि अधिकांश शिकायतें आपसी रंजिश के कारण होती है या ब्लेकमेल कर कुछ लाभ प्राप्त करने की होती है। अन्यथा यदि जहां भी अवैध खनन हो रहा है वहां के आसपास के लोग या एक्टिविस्ट सक्रिय हो जाएं तो लाख प्रयासों के बावजूद अवैध खनन नहीं हो सकता है और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को सख्ती से अवैध खनन गतिविधियों को रोकना भी चाहिए पर यह भी साफ हो जानी चाहिए कि वैध खनन को प्रोत्साहित करके ही अवैध खनन पर कारगर रोक संभव है और दूसरी यह कि सरकार के साथ ही आमजन को भी सक्रिय होने के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। यहां सरकार के पक्ष में कहने की यह बात नहीं है पर अवैध खनन गतिविधियां जहां भी हो रही है वहां के नागरिकों को भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से आगे आना चाहिए ताकि अरावली के संरक्षण में ठोस सहभागिता हो सकें।

ड्राई लैंड: धरती की सबसे नीचली जगह

हम यह तो जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे निचला प्वाइंट कहां है? यह जगह मिडिल ईस्ट के यूथोपिया के पास है।

यह जगह समुद्र तल से लगभग 100 मीटर (लगभग 1300 फीट) की गहराई में स्थित है। इसे धरती का 'ड्राई लैंड' या 'डेड सी' कहा जाता है। हालांकि धरती की सबसे गहरी जगह की बात करें तो यह समुद्र के भीतर चैलेंजर डीप है, जिसकी गहराई 35 हजार फीट है। इस जगह पर अगर माउंट एवरेस्ट को रख दिया जाए तो वह भी पानी के लेवल से नीचे ही रहेगा।

डेड सी एक गहरी झील का नाम है। इस झील का पानी बहुत खारा है और यहां सिर्फ नमक ही नमक पाया जाता है। दरअसल, यह एक बहुत बड़ी और बहुत ही खारे पानी वाली झील है।

यह लगभग 76 किलोमीटर लंबी और 18 किलोमीटर चौड़ी है। इसका नाम आखिर 'डेड सी' क्यों पड़ा? इसके नाम के पीछे की एक बहुत रोचक वजह है। दरअसल डेड सी का पानी इतना ज्यादा खारा होता है कि यहां पर कोई भी जीव-जन्तु, मछली या पानी का कोई भी जीव जिंदा ही नहीं रह पाता है।

इस झील के पानी में इतना ज्यादा नमक होता है कि यहां पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि इस झील का नाम 'डेड सी' रखा गया है। धरती का सबसे निचला इलाका 'डेड सी' ऐसी जगह पर बसा है, जहां पर धरती की दो बड़ी टैक्टोनिक प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हैं।

यह जगह अफ्रीका और अरब की सीमा पर है, जहां धरती बहुत ज्यादा धंस गई है। अनुमान लगाया जाता है कि यह जगह अब से करीब 2 करोड़ साल पहले बनी थी। यहां जमीन में बहुत बड़ी दरार है। 'डेड सी' को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर टैक्टोनिक प्लेटें सीधी होतीं तो शायद यहां की जमीन इतनी गहराई तक नहीं धंसती।

इस दरार में प्लेटों की रगड़ की वजह से हल्का सा घुमाव भी आ गया है। इस जगह से जब प्लेटें गुजरती हैं तो उनके बीच एक रिक्त स्थान छोड़ती जाती हैं। उसी रिक्त स्थान पर जमीन धीरे-धीरे धंसती चली गई और डेड सी झील की गहराई बनती चली गई।

एक और विचार के मुताबिक लाखों साल पहले धरती का एक हिस्सा अलग होकर नीचे गिर गया और उसी वजह से उसके आस-पास की जमीन धंसती चली गई। एक मत यह भी है कि किसी नक्षत्र का टूटा हिस्सा कभी समुद्र किनारे जमीन पर गिरा होगा और उसने डेड सी का रूप ले लिया।

4 अरब साल पुरानी चट्टान में छिपा धरती का 'ब्लूप्रिंट'

ग्रीनलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के दूर-दराज के इलाकों में कुछ बहुत पुरानी चट्टानें मिली हैं, जो 4 अरब साल पुरानी हैं। इन पत्थरों में खास रासायनिक गुण हैं, जो धरती पर किसी और चीज से मेल नहीं खाते। इनमें पोटैशियम-40 नाम के तत्व की मात्रा कम पाई गई है। यह तत्व ग्रहों के बनने के इतिहास को जानने के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि लगभग साढ़े 4 अरब साल पहले थिया (मंगल ग्रह के आकार का पिंड) नई बन रही पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से दोनों के पदार्थ आपस में मिल गए, जिससे चांद बना और धरती के मूल तत्व बदल गए। हालांकि यह सिद्धांत दशकों से है, लेकिन अभी तक प्रोटो-पृथ्वी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पहले सिर्फ सिमुलेशन सिद्धांत और उल्कापिंडों से तुलनाएं ही थीं। इस खोज का सबसे जरूरी हिस्सा पोटैशियम-40 है। यह एक ऐसा तत्व है जो धीरे-धीरे कम होता जाता है, इसलिए यह ग्रहों की चीजों की उम्र नापने के लिए एक प्राकृतिक घड़ी का काम करता है। इन पुरानी चट्टानों में पोटैशियम तत्वों का रेशियो अब तक जांचे गए किसी भी दूसरी धरती या अंतरिक्ष की चीज से बहुत कम था। यही वजह है कि ये चट्टानें रासायनिक रूप से सबसे अलग हैं और शायद पृथ्वी की मूल पपड़ी का सबसे पुराना बिना बदला हुआ हिस्सा हैं। इन नतीजों को पक्का करने के लिए वैज्ञानिकों ने थर्मल आयनीकरण मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम की एक खास मशीन का इस्तेमाल किया। उन्होंने चट्टानों को घोलकर उनमें मौजूद प्राकृतिक पोटैशियम तत्वों के बीच के अनुपात को जांचा। यह नई खोज पहले किए गए एक शोध पर आधारित है, जिसे ग्रह वैज्ञानिक निकोल एक्स.नी और उनके साथियों ने किया था। उन्होंने 2023 में सौर मंडल के अलग-अलग हिस्सों से आए 32 उल्कापिंडों में पोटैशियम तत्वों की जांच की थी। उन्हें पता चला कि सौरमंडल के अंदरूनी हिस्सों से आए उल्कापिंडों के रासायनिक संकेत पृथ्वी जैसे ही थे, लेकिन बाहरी सौर मंडल से आए उल्कापिंडों में बहुत बड़ा अंतर दिखा। उनमें पोटैशियम-40 की मात्रा कम या ज्यादा थी।

बढ़ते शहरों के बीच सिमट रहा बचपन, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने जताई चिंता

रवि जैन

बढ़ते शहर चाहे विकास का प्रतीक बनकर उभरे हों लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी सामने आया है जो सीधे बच्चों से जुड़ा है। तेजी से शहरीकरण के कारण शहरों में बच्चों के पास खेलने और सांस लेने की सुरक्षित जगह लगातार या तो कम होती जा रही है या बची ही नहीं है। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में इसे उजागर करते हुए कहा है कि दुनिया की करीब 44 फीसदी शहरी आबादी ही खुले सार्वजनिक स्थान के पास रह रही है। गरीब देशों में तो यह आंकड़ा महज 30 फीसदी ही है जहां लाखों बच्चों के पास खेलने और सांस लेने की सुरक्षित जगह नहीं है।

ऊंची इमारतों के बीच बच्चों की दुनिया लगातार छोटी होती जा रही है। कंक्रीट के जंगल में खेलनेए दौड़ने और खुलकर सांस लेने की जगहें खत्म हो रही हैं। डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र पयार्वास एजेंसी ने एक नई वैश्विक गाइड लाइन जारी की है जो शहरों को बच्चों के अनुकूल बनाने की जरूरत पर जोर देती है। सरकारों और नेताओं से अपील की गई है कि वे शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं बनाते समय बच्चों को केंद्र में रखें क्योंकि सार्वजनिक स्थान बच्चों के स्वास्थ्यए विकास और बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं।

अच्छी तरह डिजाइन किए गए पार्क, सड़कें और खुले मैदान बच्चों को सुरक्षित तरीके से चलने, खेलने, सीखने और प्रकृति से जुड़ने का मौका देते हैं। साथ ही ये जगहें शहरों को ज्यादा समावेशी, सुरक्षित और जलवायु.अनुकूल भी बनाती हैं।आज दुनिया की 55 फीसदी से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही है और 2050 तक यह आंकड़ा 68 फीसदी तक पहुंच सकता है। इस दौरान सबसे तेज शहरीकरण विकासशील देशों में होगा। यानी आने वाले वर्षों में ये शहर तय करेंगे कि करोड़ों बच्चों का बचपन कैसा होगा। गाइड लाइन बताती है कि सार्वजनिक स्थान बच्चों की भलाई और विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि बच्चों का सर्वोततम विकास खुली जगहों और सुविधाओं, हरित क्षेत्रों, सुरक्षित और साफ सड़कों, स्वच्छ हवाए बाहरी गतिविधियों और स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से घूमने की क्षमता तक पहुंच से मजबूत रूप से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक स्थान बच्चों की खेलने की जरूरतों और अधिकारों को पूरा करने में मदद करते हैं साथ ही उनके सामाजिक और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी का समर्थन करते हैं जो उनके रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। उनके सीखने, प्राकृतिक दुनिया में सामाजिककरण, सक्रिय जीवनशैली और स्वस्थ व्यवहार का समर्थन करते हैं। ऐसे स्थान नागरिकता को भी बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये समुदाय जीवन में अनौपचारिक भागीदारी की अनुमति देते हैं और बच्चों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 11.4 प्रतिशत थी जो 2001 की जनगणना तक बढ़कर 28.53 फीसदी हो गई। विश्व बैंक के अनुसार 2017 में यह वर्तमान में 34 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक देश की 40.76 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है।

सोशल मीडिया : वरदान भी, अभिशाप भी

अरुण मिश्रा

आधुनिक युग में सोशल मीडिया मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज का समाज सोशल मीडिया के बिना अपनी दैनिक गतिविधियों की कल्पना भी नहीं कर सकता। यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स (पूर्व ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म ने सूचनाओं के आदान-प्रदान को अत्यंत सरल और त्वरित बना दिया है। जहाँ एक ओर सोशल मीडिया ज्ञान, संवाद, रोजगार और जागरूकता का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणाम भी उतने ही गंभीर और भयावह होते जा रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया आज वरदान कम और अभिशाप अधिक सिद्ध होता प्रतीत हो रहा है।

आज वृद्ध, युवा और बालक–सभी वर्गों के लोग अपने समय का बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन पर बिताने लगे हैं। पारिवारिक संवाद, सामाजिक मेल-जोल और वास्तविक जीवन की संवेदनाएँ धीरे-धीरे आभासी दुनिया में सिमटती जा रही हैं। बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह मोबाइल फोन आ गए हैं और युवा वर्ग रील्स व लाइक्स की दुनिया में स्वयं को खोता जा रहा है। यह स्थिति समाज के मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत चिंताजनक है।

सोशल मीडिया वास्तव में एक महासागर के समान है–यदि इसमें विवेक और संयम के साथ मंथन किया जाए तो अमृत प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यदि विवेक का अभाव हो तो यही महासागर विष भी उगल सकता है। दुर्भाग्यवश आज इस महासागर से अमृत की अपेक्षा विष अधिक निकल रहा है। अश्लीलता की सभी सीमाएँ सोशल मीडिया ने पार कर दी हैं। खुलेआम आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही है, जिसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव किशोरों और युवाओं के मन-मस्तिष्क पर पड़ रहा है। नैतिक मूल्यों का क्षरण और मानसिक विकृति इसी का प्रत्यक्ष परिणाम है।

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया आज मिथ्या, भ्रामक और फेक समाचारों का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। बिना किसी पुष्टि के झूठी खबरें फैलाना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। इससे समाज में भ्रम, अविश्वास और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई बार यह फेक समाचार साम्प्रदायिक सौहार्द को भी नुकसान पहुँचाते हैं और सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करते हैं।

चिंता का विषय यह भी है कि देश-विरोधी गतिविधियाँ और राष्ट्र की एकता-अखंडता को चुनौती देने वाली सामग्री सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े सुनियोजित ढंग से प्रसारित की जा रही है। मनगढ़ंत इतिहास, विकृत तथ्यों और भ्रामक विचारधाराओं को युवाओं के समक्ष प्रस्तुत कर उनके मन में देश और संस्कृति के प्रति नकारात्मक भाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक प्रकार का बौद्धिक आतंकवाद है, जो चुपचाप समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है।

यदि समय रहते सोशल मीडिया पर प्रभावी नियंत्रण और सेंसरशिप नहीं लागू की गई, तो आने वाला भविष्य अत्यंत भयावह हो सकता है। वह दिन दूर नहीं जब समाज दिशाहीन, मूल्यविहीन और वैचारिक रूप से विभाजित हो जाएगा। इसकी कल्पना मात्र से ही मन सिहर उठता है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकार सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखे और स्पष्ट व प्रभावी नियम बनाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता की अनुमति नहीं दी जा सकती। फेक न्यूज, अश्लीलता और देश-विरोधी सामग्री पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य है। साथ ही अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग की दिशा में मार्गदर्शन मिल सके।

सोशल मीडिया न तो पूर्णतः बुरा है और न ही पूर्णतः अच्छा। यह हमारे उपयोग और नियंत्रण पर निर्भर करता है। यदि समय रहते विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए, तो यह वरदान कब अभिशाप बन जाएगा–पता ही नहीं चलेगा। अब भी समय है, चेतने का और संभलने का।

वेडिंग सीजन में दिखना है सबसे ग्लैमरस? भूमि का यह लहंगा लुक जरूर करें ट्राई!

भूमि पेडनेकर का हालिया पेस्टल पिंक लहंगा लुक वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई है। इस एलिगेंट भूमि पेडनेकर लहंगा में मॉर्डन कट ब्लाउज, डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी और स्टेटमेंट ज्वेलरी का शानदार मिश्रण है, जो आपको ग्लैमरस और रॉयल लुक दे सकता है।

बॉलीवुड डीवज के लुक्स इंस्पायर होकर आप भी फेस्टिव सीजन लेकर शादी के मौसम के लिए भूमि पेडनेकर का यह लहंगा लुक डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। फैशन लवर्स ट्रेडिंग लुक के लिए बॉलीवुड हीरोइन से प्रेरणा लेकर एक परफेक्ट ट्रेडिशनल आउटफिट को वियर कर सकते हैं। भूमि ने हाल ही में एक सुंदर-सा पेस्टल शेड के लहंगे में पोज देती नजर आई हैं। इन फोटोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इस लुक में एक्ट्रेस एलिगेंट दिख रही है। मिनिमल मेकअप लुक, स्टेटमेंट ज्वेलरी और फ्लोई सिल्हूट के साथ उनका यह लहंगा वाकई सुंदर नजर आ रहा है। इस लहंगा लुक में एक्ट्रेस रॉयल लग रही है। आप भी इस लहंगा को अपने वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं। भूमि पेडनेकर लहंगा की खासियत-

पेस्टल पिंक का चयन

फोटो में आप देख सकते हैं कि भूमि ने पेस्टल पिंक शेड को चूज किया है। फेस्टिवल से लेकर वेडिंग तक यह रंग काफी काफी ट्रेंड में है। लहंगे पर डिलेकेट व्हाइट एम्ब्रॉयडरी पूरे लुक में एथनिक ग्रेस जोड़ता है। यह व्हाइट थ्रेडवर्क इस शेड के साथ बेहतरीन कंट्रास्ट बनाता है।

मॉर्डन कट ब्रालेट डिजाइन ब्लाउज

एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल चोली की जगह एक क्रोश-इफेक्ट, मॉडर्न कट ब्लाउज पहना है। यह लहंगा एकदम इंडो-वेस्टर्न लुक प्रदान करता है।

मैचिंग दुपट्टा और ड्रेपिंग स्टाइल

एक्ट्रेस ने सॉफ्ट पिंक शेड का दुपट्टा सिंगल-साइड ड्रेप किया गया है। यह इस लुक को एकदम मिनिमल रख रहा है।

स्टेटमेंट सिल्वर-टोन ज्वेलरी

एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने चोकर, ब्रेसलेट और स्टेटमेंट ईयरस्टड्स चुनें जो आउटफिट को ग्लैम लुक दे रही है। यह ज्वेलरी लहंगा के साथ मैच कर रही है।

नेचुरल मेकअप और हेयरस्टाइल

भूमि ने न्यूड लिप्स, ग्लोई बेस और मस्कारा-फोकस्ड आईज ने लुक को सॉफ्ट और मॉर्डन टच दिया है। वहीं, स्ट्रेट ओपन हेयर लहंगे की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है।

हेयर स्टाइलिंग के बावजूद बालों को टूटने से बचाएं! एक्सपर्ट से जानें इन्हें सुरक्षित रखने के खास तरीके

फैशन के लिए हीट स्टाइलिंग का प्रयोग करने वाली लड़कियों के लिए यह लेख बालों को कमजोर होने से बचाने के खास तरीके बताता है, जिसमें हीटिंग स्प्रे का उपयोग और घरेलू हेयर मास्क से पोषण शामिल है।

आजकल लड़कियां फैशन के लिए नई-नई हेयर स्टाइल को जरुर ट्राई करती हैं। वैसे भी बालों के अलग-अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाना हम सभी को बेहद पसंद है। कई बार होता है कि हीट स्टाइलिंग टूल्स का प्रयोग करके, बालों में बाउंस या स्ट्रेट बना सकते हैं।

अत्यधिक हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बाल कमजोर होने लगते हैं। कई बार तो बालों के लिए अलग-अलग ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं, जिससे बालों में पोषण बना रहे। अगर आपको बालों को स्ट्रांग कराना है, तो इन टिप्स को फॉलों करें।

हीट स्टाइलिंग से कमजोर हुए बालों को स्ट्रांग बनाने की टिप्स

जब भी आप हीट स्टाइलिंग टूल्स का प्रयोग कर रही हैं, तो आप हीटिंग सेटिंग स्प्रे का यूज

कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके बालों में हीट कम लगती है। इसके साथ ही आपके बाल खराब नहीं होते हैं। हीटिंग स्प्रे आपको बाजार में मिल जाएंगे। इसे पहले बालों में लगाकर फिर हीटिंग टूल्स का प्रयोग करें। इसके प्रयोग से आपके बाल डैमेज नहीं होंगे।

बालों को पोषण जरुर दें

यदि आप बालों में ज्यादा हीटिंग टूल का प्रयोग करती है, तो इससे पहले अपने बालों को पोषण जरुर दें। इसके लिए आप घर में बनें हुए सीरम या हेयर मास्क का प्रयोग कर सकती हैं। इसके बाद ही हीट स्टाइलिंग का इस्तेमाल करें।

ऐसा करने से आपका स्कैल्प कमजोर नहीं होगा और बाल भी मजबूत बनें रहेंगे। आपके हेयर्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। बस आपको समय-समय पर अपनी चीजों का इस्तेमाल करना जरुरी है।

रात को करें ये हेयर रुटीन फॉलो

अगर आपके हेयर्स हीटिंग टूल्स के प्रयोग से ज्यादा ही खराब हो रहे है, तो आप रात के समय हेयर केयर रुटीन जरुर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको बालों के टूटने की समस्या कम हो जाती है। आप हफ्ते में कम से कम 2 बार गरम तेल से बालों की मालिश करें। इसके बाद हेयर वॉश करें। ऐसा करने से आपके बालों को नमी मिलेगी।

प्रेम का प्रतीक राजा नल का किला

मध्यप्रदेश में शिवपुरी से 30 किमी दूर 500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना राजा नल का किला, जिसे नरवर किले के नाम से जाना जाता है, 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह किला नल-दमयंती की प्रेमकथा की याद दिलाता है।

राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानी तो आपने सुनी ही होगी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में नरवर किले में इस प्रेमी जोड़े की प्रतिमाएं स्थापित किये जाने की चर्चा के साथ उनकी प्रेमकथा एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। यह किला राजा नल का ही है। महाभारत काल में राजा नल की राजधानी नलपुरा (निषध नगर) थी। समय के साथ 'नलपुरा' का नाम बदलकर 'नरवर' हो गया। यह किला कई राजवंशों का साक्षी रहा है, लेकिन इसकी पहचान आज भी राजा नल और रानी दमयंती से ही जुड़ी है।

इस किले की चोटी पर राजा नल और रानी दमयंती की इतनी विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जा गई हैं कि किले के हर कोने से दिखाई देती हैं। महाभारत काल में एक प्रमुख नगर के रूप में जाना जाने वाला नरवर नल-दमयंती की प्रतिमाएं स्थापित होने के बाद पर्यटन मानचित्र पर छा रहा है। शिवपुरी मुख्यालय से 30 किमी. दूर 500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है नरवर का प्राचीन किला। यह किला 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है।

शिवपुरी से नरवर पहुंचने के लिये लम्बी चढ़ाई के बाद किले तक पहुंचा जा सकता है. लेकिन जब नजरें किले की खूबसूरती को देखती हैं तो ऊंची चढ़ाई की थकान खत्म हो जाती है। नरवर किले का पूरा क्षेत्र चार स्थानों में बंटा हुआ है। ये चार स्थान हैं मचलोक, मदार, गजूर और ढोल अहाता। किले के चारों तरफ मन को मोह लेने वाली हरियाली है। किला चारों तरफ से पहाड़ों और जंगल से घिरा हुआ है।

जैसे ही किले के प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखेंगे, आपका स्वागत 'छिप महल' से होगा, जो जटिल नक्काशीदार स्तंभों से सुसज्जित है। किले के भीतर हवापौर महल, कोरियों की हवेली, लड़ाऊ बंगला, फुलवा महल और भूलभुलैया मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। नरवर किले का आंतरिक भाग, जो अनुप्रस्थ दीवारों द्वारा 'अहाता' और 'ढोलाहाता' नामक चार खंडों में विभाजित है। राजपूत शैली की वास्तुकला से युक्त इसकी

नरवर किले की यात्रा न केवल इतिहास की यात्रा है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खोज भी है।

विशेषताएँ सपाट छतें, नालीदार स्तंभ और बहु-स्तरीय मेहराब हैं। किले का स्वरूप बत्तख की गर्दन, सिर और चोंच जैसा है, जिसका मध्य भाग माझ महल के रूप में जाना जाता है। उत्तरी भाग में संत शाह मदार की दरगाह है।

किले की जटिल भूलभुलैया से गुजरते आपको महाभारतकाल के चिन्हों से लेकर 1857 के गदर तक का इतिहास देखने को मिलेगा। अंग्रेजों से सन् 57 के विद्रोह में तात्या टोपे की वीरता का गवाह है यह किला। लगभग आठ किलोमीटर तक फैली दीवारों के साथ नरवर किला एक दुर्जेय वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़ा है, जो साहसी और इतिहास प्रेमियों दोनों को आकर्षित करता है। नरवर किले की यात्रा न केवल इतिहास की यात्रा है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खोज भी है।

नरवर पहुंचने के लिए पहले आपको शिवपुरी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। इसके बाद अपने निजी या किसी अन्य वाहन से 30 किलोमीटर का सफर कर नरवर पहुंच सकेंगे। नरवर किले पर घूमने के लिये 20 रुपये का टिकट लेना होगा। यह शुल्क किले की देखरेख और साफ-सफाई के निमित्त लिया जाता है।

क्या है नल-दमयंती की प्रेमकथा

विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषध के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही बहुत सुंदर थे। दोनों ही एक-दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही एक-दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इन्द्र, वरुण, अग्नि और यम भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। वे चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप धारण करके आए। नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देख दमयंती घबरा गईं, लेकिन उनके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उन्होंने देवाताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। नल-दमयंती का मिलन तो होता है, पर कुछ समय बाद वियोग भी हो जाता है। दोनों बिछुड़ जाते हैं। नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है और दोनों बिछुड़ जाते हैं। दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है और बाद में अपने परिवार में पहुंच जाती है। उनके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती से बिछुड़ने के बाद नल को कर्कोटक नामक सांप ने डस लिया, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था और उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। वे बाहुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचे। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल नहीं था। उन्होंने नल को पहचान लिया। बाद में पुष्कर से पुन: जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी जीत ली। दमयंती न केवल रूपसी थीं, बल्कि उनका प्रेम भी इतना अटूट था कि उन्हें देवताओं का रूप-वैभव भी विचलित नहीं कर सका और ना ही पति का विरूप हुआ चेहरा उनके प्यार को कम कर पाया था।

महंगे प्रोबायोटिक भूल जाएं, मात्र बस 10 रुपए में सुधारें अपने पेट का हेल्थ

डॉ. निमित त्यागी

अगर आपका पेट ठीक है, तो इम्यूनिटी, दिमाग और मूड सब सही रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट को हेल्दी रखने के लिए आपको किसी महंगे प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ सादे और सस्ते फर्मेंटेड फूड्स ही काफी हैं।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जिस कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खराब खानपान की वजह से पेट को ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अधिकतर लोग गैस, पेट की तकलीफ या कब्ज जैसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पेट यानी की गट ही हमारी पूरी सेहत की जड़ है।

अगर आपका पेट ठीक है, तो इम्यूनिटी, दिमाग और मूड सब सही रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट को हेल्दी रखने के लिए आपको किसी महंगे प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ सादे और सस्ते फर्मेंटेड फूड्स ही काफी हैं।

जो 10 रुपए से कम में आपका पेट फिट रख सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको तीन आसान फर्मेंटेड फूड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

फर्मेंटेड राइस कांजी

यह एक सस्ती, देसी और असरदार रेसिपी है। जोकि पेट की सफाई तो करती है, साथ ही यह डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। फर्मेंटेड राइस कांजी बनाने के लिए दो चम्मच पके हुए चावल और दो चम्मच दही को एक गिलास पानी में मिलाना होगा।

इसको रातभर ढककर रख दें, जिससे कि यह फर्मेंट हो जाए। अब सुबह इसको अच्छे से मसलें या फिर ब्लेंड कर लें।

इसके बाद इसमें नमक डालें और चाहें तो बारीक कटी हरी मिर्च और प्याज डाल सकती हैं। अब इसको डाइट में शामिल करें, इसमें मौजूद नेचुरल बैक्टीरिया आंतों की लाइनिंग को हील करते हैं और डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं।

फर्मेंटेड रागी कांजी

वहीं रागी अपने आप में एक सुपरफूड है। जब इसको फर्मेंट किया जाता है, तो इसका फायदा दोगुना हो जाता है। रागी कांजी बनाने के लिए आपको 4 चम्मच रागी आटे में आधा कप पानी मिलाकर पतला सा घोल तैयार कर लें।

फिर एक पैन में दो कप पानी उबालें और धीरे-धीरे रागी घोल डालते हुए चलाते रहें। अब करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब यह ठंडा हो जाए, तो इसको कांच या मिट्टी के बर्तन में डालें। इसको रात भर ढककर रखें। सुबह इसमें थोड़ा सा नमक, मट्ठा, हरी मिर्च और प्याज डालकर पिएं। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स हड्डियों और पेट दोनों के लिए फायदेमंद है।

दही या ग्रीक योगर्ट

बता दें कि अगर आप जल्दी में हैं, तो यह सबसे आसान तरीका है। लंच के बाद एक कटोरी दही खाएं। अगर आ ग्रीक योगर्ट लेते हैं, तो इसमें 12 ग्राम तक प्रोटीन भी मिलता है, यह शरीर को एनर्जी देता है और पाचन को आसान बनाता है।

घर के सदाबहार फूल में छुपा है डायबिटीज कंट्रोल का राज, ऐसे करें सेवन

डॉ. मुकुल शर्मा

सदाबहार का फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। सदाबहार की पत्तियां और फूलों में एल्कलॉइड पाया जाता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसको डाइट में कैसे शामिल करना है।

डायबिटीज को कंट्रोल करने में सही डाइट का मुख्य रोल होता है। अक्सर लोगों का मानना होता है कि सिर्फ मीठा खाने से शुगर बढ़ता है और यदि आप मीठा खाना छोड़ देते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भले ही मीठा खाने या न खाने से ब्लड शुगर लेवल पर इसका असर होता है, लेकिन यह डायबिटीज को मैनेज करने के लिए काफी नहीं होता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में कई फल-फूल, सब्जियां और मसाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन्हीं में से एक सदाबहार का फूल है। यह फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। सदाबहार की पत्तियां और फूलों में एल्कलॉइड पाया जाता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसको डाइट में कैसे शामिल करना है और यह ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करता है।

डायबिटीज कंट्रोल करेगा सदाबहार का फूल

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो सदाबहार यानी की कैथेरेन्थस रोजियस एक साधारण पौधा है। लेकिन यह साधारण सा पौधा ब्लड शुगर को बैलेंस करने में सहायता करता है। इसमें एल्कलॉइड्स इंसुलिन पाया जाता है, जो कि सेंसिटिविटी को सुधारते हैं और इससे पेनक्रियाटिक सेल्स को प्रोटेक्शन मिलता है। सदाबहार की फूल और पत्तियां सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाने में सहायता करता है।

इसमें हाइपोग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं, जोकि ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं। वहीं इसके सेवन से इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ता है। इनके सेवन से बीटा-पैंक्रियाद सेल्स से इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है और यह बॉडी को डिटॉक्स करने में सहायता करता है और इससे खून भी साफ होता है।

सदाबहार के फूल और पत्तियों को डाइट में करें शामिल

बता दें कि खाली पेट सदाबहार के फूल की दो-तीन पत्तियों को चबाना चाहिए। रोजाना सदाबहार की पत्तियों का 1-2 चम्मच जूस पिएं।

इसके अलावा आप 1-2 सदाबहार के फूल को पानी में उबालकर इसको दिन में 1 बार पिएं।

सदाबहार की पत्तियों का पाउडर दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन करना चाहिए।

सदाबहार के फूल और पत्तियों को इस तरह से डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि इनका अधिक मात्रा में सेवन न करें, साथ ही सही डाइट पर भी ध्यान दें।

अपनी एक्टिंग से लोगों को अपनी ओर आक्रशित कर रहीं गिरिजा ओक

टीवी पर 'प्यूरो नमक' का विज्ञापन देने वाली एक्ट्रेस गिरिजा ओक नीली साड़ी में कुछ फोटो वायरल होने के बाद रातों-रात सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश बन गईं हैं। उनकी खूबसूरती की जबरदस्त तारीफ की जा रही है। लेकिन अब यही पॉपुलरिटी इस अभिनेत्री की परेशानी बन गई है।

कम ही लोगों को पता होगा कि टीवी पर प्यूरो नमक का विज्ञापन देने वाली अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले करीब 20 साल से फिल्मों में एक्टिंग कर रही हैं। टीवी से शुरू हुआ उसका यह सफर फिल्मों के होते हुए आज सोशल मीडिया पर भी छा गया है। हाल ही में गिरिजा की कुछ तस्वीरें वायरल हुईं और उन्हें सोशल मीडिया पर रातों-रात नेशनल क्रश घोषित कर दिया गया। हालांकि उनकी यही पॉपुलेरिटी उनके लिये परेशानी का सबब बन गई है।

पिछले दिनों किसी ने एआई की मदद से बनाई गई गिरिजा ओक की उन तस्वीरों को वायरल कर दिया, जो न केवल भद्दी हैं, बल्कि पूरी तरह से एडिटिड हैं। इन वायरल तस्वीरों से परेशान गिरिजा ने एक वीडियो बनाकर अपनी चिंता और नारजगी जाहिर की है। इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर कर गिरिजा ओक ने दर्शकों से मिले प्यार और प्रशंसा का जिक्र किया और इसे 'पागलपन और शानदार' दोनों बताया। उन्होंने जहां प्यार के लिए आभार व्यक्त किया, वहीं अश्लील फोटो वायरल किये जाने पर नाराजगी और चिंता जताई।

गिरिजा ने कहा कि एआई की मदद से बनाईं उनकी फर्जी तस्वीरें हद से ज्यादा कामुक और अश्लील हैं, जिनमें उन्हें एक वस्तु के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि वे खुद सोशल

फिल्म समीक्षक भी करते हैं ब्लैकमेलिंग

फिल्मों के रिलीज होने से पहले उनकी समीक्षा करने वाले समीक्षक जमकर ब्लैकमेलिंग करते हैं। यह सच्चाई हाल ही में मल्टीकास्ट फिल्म 'धुरंधर' को लेकर उजागर हुई है। अभिनेत्री यामी गौतम ने खुलासा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में मार्केटिंग कराने के नाम पर समीक्षक निमार्ताओं से जबरन वसूली करते हैं। यह ब्लैकमेलिंग भारतीय सिनेमा के लिये बड़े खतरे का संकेत है और इसके खिलाफ पूरी इंडस्ट्री को एकजुट होना होगा। यामी की इस बात पर रितिक रोशन जैसे दिग्गज अभिनेता ने सहमति जताई है। दरअसल यामी गौतम फिल्म धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर की पत्नी हैं और उन्होंने इस फिल्म की मार्केटिंग के लिये वसूली से इनकार कर दिया तो समीक्षकों ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसकी बुराई करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि एडवांस बुकिंग के वक्त फिल्म की उम्मीद से कम ही टिकटें बिक सकीं। हालांकि सप्ताह के अंत में दर्शकों ने समीक्षकों की रेटिंग को दरकिनार कर दिया और आखिरकार अच्छी मार्केट मिल ही गई। यामी ने कहा कि फिल्म मेकरों के लिये यह वक्त आ गया है कि वे ब्लैकमेलरों के मुखौटे उजागर करने का अभियान छेड़ें और उनकी निगेटीविटी की असलियत दर्शकों के सामने लाएं। यामी ने इस ब्लैकमेलिंग को फिल्म इंडस्ट्री के लिये 'प्लेग' की संज्ञा दी है।

मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और ऑनलाइन ट्रेंड कैसे काम करते हैं, इससे पूरी तरह वाकिफ हैं। गिरिजा ओक का कहना है कि 'जब कोई चीज वायरल होती है, तो उसका मतलब होता है। इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर तब तक बनती और प्रसारित होती रहती हैं, जब तक लोग आपकी पोस्ट पर क्लिक करते हैं और आपको पर्याप्त लाइक, इंटरैक्शन और व्यूज मिलते रहते हैं।

हम सब जानते हैं कि यह खेल कैसे खेला जाता है।' उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से होती है कि इस 'खेल के कोई नियम नहीं हैं' और इस खेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी 'अनुमति न हो'। उन्होंने एक 12 साल के बेटे की मां होने के नाते अपनी चिंता व्यक्त की। वे कहती हैं कि 'मेरा बारह साल का बेटा है। वह अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आगे चलकर करेगा। जब वह बड़ा हो जाएगा, तो उसे इन तस्वीरों तक पहुंच मिल जाएगी। तब वह अपनी मां के बारे में क्या सोचेगा?

गिरिजा कहती हैं कि 'अपनी मां की अश्लील तस्वीरें मेरा बेटा एक दिन देखेगा। यह सोचकर मुझे चिंता होती है, डर लगता है। यह सोचकर मैं परेशान होती हूं कि वह इनके बारे में कैसा महसूस करेगा? उसे पता चल जाएगा कि ये असली तस्वीरें नहीं हैं और इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से मॉर्फ किया गया है। ठीक वैसे ही, जैसे जो लोग अभी ये तस्वीरें देख रहे हैं। यह डिजिटलीकरण न केवल डरावना है, बल्कि हर अभिनेता-अभिनेत्री और पेशेवर लोगों को इसकी चिंता करनी होगी।' यह खेल परिवारों को तहस-नहस करने वाला है। सरकार को इसके खिलाफ कड़े कानून बनाने होंगे, ताकि कोई किसी की छवि खराब न कर सके।

मराठी अभिनेता गिरीश ओक की बेटी गिरिजा ओक हिंदी और मराठी दोनों सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 2007 में आमिर खान और दर्शील सफारी अभिनीत फिल्म 'तारे जमीन पर' में देखा गया था। वह 'शोर इन द सिटी', नेटफ्लिक्स फिल्म 'कला', 'द वैक्सीन वॉर' और शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में अभिनय कर चुकी हैं। उन्हें अच्छी अभिनेत्री के तौर पर देखा जाता है।

एक युग खत्म...

साइना नेहवाल की चुपचाप विदाई ने खेल जगत को सन्न कर दिया

साइना नेहवाल के अंतरराष्ट्रीय करियर का पर्दा एक चुपचाप विदाई के साथ गिर गया...बिना शोर, बिना समारोह, बस एक शांत ऐलान जिसने खेल जगत को सन्न कर दिया. भारतीय बैडमिंटन में स्वर्णिम युग का पर्याय रहीं साइना ने अपने अकेले दम पर उस दौर में रास्ता बनाया जब बैडमिंटन भारत में मुख्यधारा नहीं था।

महमूद रजा
बिजनौर

भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और देश में इस खेल की सबसे पहचान बनाने वाली शख्सियतों में शामिल साइना नेहवाल ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया. लंबे समय से चली आ रही घुटने की गंभीर समस्या और रिकवरी न हो पाने की स्थिति ने आखिरकार उन्हें ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया की बजाय एक पॉडकास्ट के दौरान साइना ने कहा कि उनके घुटनों में अत्यधिक डीजेनरेशन हो चुका है, जिस कारण उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संभव नहीं रह गया था।

साइना का यह ऐलान एक ऐसे अध्याय का अंत है जिसने भारतीय बैडमिंटन की कथा ही बदल दी।21 साल लंबे करियर में ओलंपिक पदक, विश्व चैम्पियनशिप का मंच, विश्व नंबर-1 रैंकिंग और 10 सुपर सीरीज खिताब- ये सभी उपलब्धियां इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए दुर्लभ ही थीं।

साइना ने रिटायरमेंट की घोषणा ऐसे समय की जब वह पिछले कई महीनों से अंतरराष्ट्रीय सर्किट से बाहर थीं। उनकी आखिरी प्रतिस्पर्धी उपस्थिति सिंगापुर ओपन 2023 में रही थी। इसके बाद बार-बार चोट लौटने और सर्जरी की सलाह ने उनकी वापसी की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया।

सबसे दिलचस्प यह रहा कि साइना ने इस फैसले को किसी बड़े मंच, प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नहीं बताया. यह उस तरह की नाटकीय विदाई नहीं थी जो अक्सर दिग्गजों को मिलती है। बल्कि यह एक चुपचाप लिया गया फैसला था, ठीक वैसे ही जैसे साइना ने अपने करियर में ज्यादातर बातें कीं- खेल के जरिए, बयान के जरिए नहीं।

पॉडकास्ट में साइना ने स्वीकार किया कि उन्होंने कई महीने तक यह परखने की कोशिश की कि क्या शरीर रिटर्न करने की स्थिति में है। लेकिन घुटने की गंभीर स्थिति और लगातार दर्द ने इस कोशिश को असंभव बना दिया। उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा चोटों से लड़कर वापसी की है, लेकिन इस बार शरीर ने साफ संकेत दे दिए।'

ओलंपिक पदक और उस दौर की याद

साइना के करियर का सबसे चमकदार पन्ना लंदन ओलंपिक 2012 में आता है, जहां उन्होंने भारत के लिए बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक (कांस्य) जीता। इस पदक की खनक ने भारतीय बैडमिंटन को नए दौर में प्रवेश करवाया। इसी दौर में पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय जैसे खिलाड़ियों ने भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत की। खेल विशेषज्ञों की राय में, 'यदि सिंधु ने भारत के बैडमिंटन को ऊंचाई पर बनाए रखा है, तो उस ऊंचाई तक उसे पहुंचाने वाली खिलाड़ी का नाम साइना है।'

चोटों से जंग और मजबूरी की विदाई

रियो 2016 ओलंपिक से ठीक पहले लगी घुटने की चोट ने साइना के करियर को बुरी तरह प्रभावित किया। सुधार के बाद उन्होंने 2017 और 2018 में शानदार वापसी की, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड और विश्व चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज शामिल रहे। लेकिन घुटने ने फिर साथ छोड़ना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के एक पूर्व साथी खिलाड़ी ने टिप्पणी की, 'साइना किताब बंद नहीं करना चाहती थीं, लेकिन पन्ने पलटने को उनके हाथ में भी ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे।'

भारत के लिए एक विरासत पीछे छोड़ गईं साइना

साइना सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक जनरेटर थीं- भारतीय बैडमिंटन में विश्वास का, आत्मसम्मान का और महत्वाकांक्षा का।

24 अंतरराष्ट्रीय खिताब,वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग,ओलंपिक और विश्वस्तरीय मेडल और सबसे अहम- एक पूरी पीढ़ी को रैकेट उठाने की वजह। आज भारत में हर बड़ी बैडमिंटन अकादमी में छोटे-छोटे बैग लेकर पहुंचने वाली बच्चियों की आंखों में जो चमक दिखती है, उसमें कहीं न कहीं साइना की कहानी ही दर्ज है।

साइना का रिटायरमेंट भारतीय खेल कैलेंडर से एक नाम कम कर गया है, लेकिन भारतीय खेल संस्कृति में एक विरासत जोड़ गया है। अब जबकि उनके रैकेट ने दीवार का सहारा पकड़ लिया है, यह देश उस खिलाड़ी को सलाम कर रहा है, जिसने यह साबित कर दिया कि बेटियां पदक नहीं, परिवर्तन लाती हैं।

CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.
VCB PANEL, CRP,
TRANSFORMER, RMU ETC

SECURE METERS LTD.
ENERGY METER
(POSTPAID/PREPAID/
SOLAR/ABT)

SECURE

MITSUBISHI ELECTRIC
MCB/MCCB/ACB/
CONTRACTOR/DB

MITSUBISHI ELECTRIC

Kumar Enterprises

GF-150 | DURGA TOWER | RDC | RAJ NAGAR | GHAZIABAD (UP) - 201001
TEL. : 0120-4137613 | EMAIL : ke.ghaziabad@gmail.com
SANJEEV KUMAR 9268566079

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

भारत की पहली
रैपिड रेल सेवा

मेरठ से दिल्ली तक 'नमो भारत' का संचालन

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

UPGovtOfficial
CMOUttarpradesh
CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश